नई दिल्ली ■ शनिवार 06 दिसंबर 2025 ■ मूल्य 5.00 ■ वर्ष 13 ■ अंक 248 ■ पृष्ठ 08

JBT जनभावना टाइम्स

www.thejbt.com

निष्पक्ष और निर्भीक खबर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल एवं करनाल से प्रकाशित

04 जीएसटी सुधार से हुआ चमत्कार | 07 रोहित-कोहली से फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद | पति आदित्य की फिल्म 'धुरंधर' के रिलीज के दिन भावुक हुई यामी गौतम 08

भारत-रूस दोस्ती 'ध्रुव तारे के समान': मोदी

भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए संकल्पबद्ध : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को भारत-रूस संबंधों की तुलना आकाश में एक स्थान पर स्थिर बने रहने वाले ध्रुव तारे से की। उन्होंने कहा कि दोनों देश 2030 तक अपने आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश यूरेशिया (एशिया-यूरोप) आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शुक्रवार को यहां के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय शिखर वार्ता की।

वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 दशकों में विश्व ने उतार-चढ़ाव देखे हैं और मानवता अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरी है लेकिन भारत और रूस की मित्रता ध्रुव तारे की तरह परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिकी है और समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंध को मजबूत बनाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मीडिया वक्तव्य के दौरान इन समझौतों का आदान-प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत शीघ्र ही रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 दिनों के टूरिस्ट वीजा और ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने दुर्लभ खनिजों में दोनों देशों के सहयोग को पूरे विश्व में सप्लाई चैन की सुरक्षित और विविधता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे स्वच्छ ऊर्जा, उच्च तकनीकी उत्पादन और आने वाले समय के उद्योगों में हमारी साझेदारी को समर्थन देंगे।

प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा को भारत रूस साझेदारी का महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ बताया और कहा कि नागरिक नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों का दशकों पुराना सहयोग स्वच्छ ऊर्जा की हमारी सामाजिक प्राथमिकता को सार्थक बनाने के लिए महत्वपूर्ण रहा है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दोनों देश समुद्री यात्रियों के ध्रुवीय जल में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि इस वर्ष अक्टूबर में लाखों श्रद्धालुओं को

बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बिना रुकावट ईंधन शिपमेंट जारी रहेगा : पुतिन

नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रेड समेत अन्य मुद्दों पर वार्ता की। इस दौरान भारत और रूस के बीच कई समझौते हुए हैं। बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस को संबोधित किया। वहीं रूसी नेता ने भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी का ऑफर भी दिया है। रूस और भारत के बीच कई समझौते हुए हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने दस्तावेज एक्सचेंज किए। स्वास्थ्य, शिपिंग और टैक्सेशन को लेकर दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी का ऑफर भी दिया है। सहयोग और माइग्रेशन, दूसरे राज्य के इलाके में शहरी नागरिकों की अस्थायी श्रम गतिविधियों को लेकर भी बात बनी है। पुतिन ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, "मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मेरे प्यारे दोस्त पीएम मोदी और भारत के लोगों को रूसी डेलिगेशन के गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी के साथ डिनर पर मेरी बातचीत हमारी खास रणनीतिक पार्टनरशिप के लिए बहुत मददगार रही। पीएम मोदी और मैंने एक करीबी वर्किंग डायलॉग बनाया है। हम एससीओ समिट के दौरान मिले थे और हम खुद रूस-भारत डायलॉग की देखरेख कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, "पिछले साल, हमारे द्विपक्षीय व्यापार के टर्नओवर में 12 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। हम अभी अनुमान लगा रहे हैं कि इस साल का व्यापार समझौता उसी शानदार स्तर पर रहेगा।" उन्होंने कहा, "हम बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन का बिना रुकावट शिपमेंट जारी रखने के लिए तैयार हैं। हम कुडनकुलम में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। छह में से दो रिएक्टर यूनिट पहले से ही ग्रिड से जुड़ी हुई हैं, जबकि चार और बन रही हैं। इस प्लांट को पूरी क्षमता में लाने से भारत की ऊर्जा जरूरतों में एक बड़ा योगदान मिलेगा; इससे उद्योगों और घरों को सस्ती और साफ बिजली मिलेगी। हम छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट और दवाई और कृषि जैसे क्षेत्रों में तकनीक के इस्तेमाल पर बात कर सकते हैं।

आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद : पुतिन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उन्हें भारत आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान पुतिन ने कहा, ₹प्रिय प्रधानमंत्री, प्रिय दोस्तों, सबसे पहले, निमंत्रण और कल की बहुत अच्छी शाम के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।₹ यूक्रेन मुद्दे पर शांति के प्रति रूस की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए पुतिन ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत में चल रहे इस कामकाजी दिन से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। उन्होंने रूस और भारत के बीच गहरे संबंधों का उल्लेख किया और यूक्रेनी मुद्दे को हल करने में मदद करने के लिए मोदी के प्रयासों की सराहना की।

महात्मा गांधी ने विश्व शांति के लिए अमूल्य योगदान दिया: राष्ट्रपति पुतिन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति ने एक विजिटर बुक पर हस्ताक्षर भी किया, जिस पर एक संदेश लिखा था। महात्मा गांधी के लिए दिए संदेश में पुतिन ने लिखा कि आधुनिक भारत के संस्थापकों में से एक के रूप में उन्होंने विश्व शांति के लिए अमूल्य योगदान दिया। राजघाट परिसर के सम्मानीय विजिटर्स की बुक पर हस्ताक्षर करते हुए, पुतिन ने कहा कि महात्मा गांधी ने नए, ज्यादा न्यायपूर्ण, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंदाजा लगाया था जो अभी अपने शुरुआती दौर में है। महात्मा गांधी के रूस के साथ कई जुड़ाव थे जो दोनों देशों के साझा इतिहास का हिस्सा हैं।

आठ दशक की स्थिर मित्रता का नया अध्याय

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस की मित्रता पिछले आठ दशकों से ध्रुव तारे की तरह अडिग रही है। यह रिश्ता आपसी सम्मान, गहरे विश्वास और समय की कसौटी पर खरे उतरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के संबंध कई ऐतिहासिक पड़ावों से गुजर रहे हैं।

एफटीए पर तेजी और आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई

मोदी ने बताया कि भारत और रूस यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को शीघ्र पूरा करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। यह समझौता होने पर दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में बड़ा विस्तार होगा और आर्थिक साझेदारी नई ऊंचाई तक पहुंचेगी।

100 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य और ऊर्जा सुरक्षा पर रूस का आश्वासन

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वार्ता के दौरान कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को सालाना 100 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर तक ले जाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को व्यापक और संतुलित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुतिन ने यह भी आश्वासन दिया कि रूस भारत को ईंधन की निर्बाध आपूर्ति के लिए तैयार है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।

यूक्रेन संकट पर भारत की शांति की नीति दोहराई

प्रधानमंत्री मोदी ने रूस को यह भी आश्वस्त किया कि भारत शुरू से ही यूक्रेन मसले पर संवाद और शांति का समर्थक रहा है। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन में शांति स्थापना के लिए अपना योगदान देने को तैयार रहा है और आगे भी यही भूमिका निभाएगा। भारत और रूस के बीच हुए ये समझौते निकट भविष्य में द्विपक्षीय सहयोग को और व्यापक, व्यवहारिक और परिणाम-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

काल्मिकिया में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मंच में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आशीर्वाद मिला। यूक्रेन संघर्ष पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शुरुआत से ही शांति का पक्षधर रहा है। हम विषय के शांतिपूर्ण, स्थाई समाधान के लिए किये जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार है और आगे भी जारी रखेगा। आतंकवाद पर एक बार फिर कड़ा रुख जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ लड़ाई में भारत-रूस लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्य पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने विश्वास जताया कि हमारी मित्रता वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को समृद्ध करेगा।

संक्षिप्त खबरें

चंपावत में सड़क हादसा, पांच बारातियों की मौत, पांच घायल

चंपावत। पाटी ब्लॉक क्षेत्र से बारात लौटते समय एक बोलेरो कार के गहरी खाई में गिरने से हादसा हो गया। वाहन घाट के पास बागधार में अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर नीचे जा लुढ़का, जिसमें 5 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक ही परिवार के दो सदस्य भी शामिल हैं। पुलिस, एसडीआरएफ एवं स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर बड़ी मशक्कत के बाद शवों और घायलों को खाई से बाहर निकाला। सभी घायलों को उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट पहुँचाया गया है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए लाया जा रहा है। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। मृतकों में प्रकाश चंद्र उनियाल (40 वर्ष) निवासी दिबडिब्बा विलासपुर, केवल चंद्र उनियाल (35 वर्ष) निवासी निवासी दिबडिब्बा विलासपुर, सुरेश नौटियाल (32 वर्ष) निवासी पंतनगर, प्रियांशु चौबे (6 वर्ष) पुत्र सुरेश चौबे, निवासी सियालदेह, भिक्यासेन, अल्मोड़ा व भावना चौबे (28 वर्ष) पत्नी सुरेश चौबे, निवासी सियालदेह, बिखयासेन, अल्मोड़ा शामिल हैं। दुर्घटना में देवीदत्त पांडेय (38) पुत्र रामदत्त पांडेय, सेराघाट (अल्मोड़ा) चालक, धीरज उनियाल (12) पुत्र प्रकाश चंद्र उनियाल, रुद्रपुर, राजेश जोशी (14) पुत्र उमेश जोशी, बनकोट गंगोलीहाट, चेतन चौबे (5) पुत्र सुरेश चौबे, दिल्ली व भास्कर पंडा, पुत्र रमेश पंडा, सेराघाट गंगोलीहाट घायल हो गये।

अनमोल बिश्नोई की हिरासत सात दिनों के लिए बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) हिरासत 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। सुरक्षा के लिहाज से पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने खुद एनआईए मुख्यालय जाकर सुनवाई की। इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई की एनआईए हिरासत 5 दिसंबर तक बढ़ाई थी। एनआईए के वकील राहुल त्यागी ने अनमोल बिश्नोई की हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि उससे अभी और पूछताछ करने की जरुरत है, ताकि कुछ और खुलासा हो सके। उसके बाद कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई की एनआईए हिरासत 7 दिन और बढ़ाने का आदेश दिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अनमोल बिश्नोई 2022 में ही फर्जी पासपोर्ट के आधार पर अमेरिका भाग गया था।

आरबीआई ने रेपो दर 0.25% घटाई, कर्ज होंगे सस्ते

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को वृहद आर्थिक स्थिति और वैश्विक परिस्थितियों पर गौर करते हुए प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.25 प्रतिशत घटाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने अमेरिकी शुल्क के प्रभावों से निपटने के लिए 'बेहद संतुलित' अर्थव्यवस्था को समर्थन देने वाले कदमों की भी घोषणा की। आरबीआई के रेपो दर में कटौती से आवास, वाहन और वाणिज्यिक कर्ज सस्ता होने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया। इसके अलावा महंगाई दर के अनुमान को 2.6

प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है। इस तरह वर्ष 2025 में रेपो दर में अब तक कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की जा चुकी है। इससे पहले, केंद्रीय बैंक ने इस साल फरवरी से जून तक रेपो दर में कुल एक प्रतिशत की कटौती की थी। वहीं अगस्त और अक्टूबर में मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया था। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने छह-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीस) की तीन-दिवसीय बैठक में लिए गए इन निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, ''एमपीसी ने आम सहमति से रेपो दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 5.25 प्रतिशत करने का निर्णय किया है।₹ रेपो दर में इस कटौती से आरबीआई ने डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 90 के भी पार चले जाने से जुड़ी आशंकाएं दरकिनार करने की कोशिश की है। इस साल डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में पांच प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है जो एशिया की सभी मुद्राओं के बीच सबसे खराब प्रदर्शन है। रेपो वह ब्याज दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने मौद्रिक नीति के रुख को तटस्थ बनाए रखने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक स्थिति के हिसाब से नीतिगत दर में समायोजन को लेकर लचीला बना रहेगा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है। वहीं चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को घटाकर 2.0 प्रतिशत कर दिया गया जबकि पहले इसके 2.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया था।

ईडी ने की रिलायंस समूह की और संपत्तियां कुर्क

नई दिल्ली। रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ चल रही धनशोधन जांच के तहत ईडी द्वारा कुर्क की नयी संपत्तियों में मुंबई में रिलायंस सेंटर, एक गेस्टहाउस और कुछ आवासीय संपत्तियां, चेन्नई में 231 भूखंडों समेत 1,120 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि ये संपत्तियां 'रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और 'रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड की हैं तथा यह धनशोधन जांच यस बैंक में कथित धोखाधड़ी से जुड़ी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने इससे पहले इस कारोबारी समूह की 8,997 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की थी तथा ताज़ा कार्रवाई के साथ, रिलायंस समूह की कुल कुर्क संपत्ति का मूल्य 10,117 करोड़ रुपये हो गया है।

लाल किला विस्फोट मामला: आरोपी सोयब की एनआईए हिरासत 10 दिन बढ़ाई गई

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले में आत्मघाती बम हमलावर उमर-उन-नबी की मदद करने के आरोपी फरीदाबाद के निवासी सोयब की एनआईए हिरासत की अवधि शुक्रवार को 10 दिन के लिए बढ़ा दी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने 26 नवंबर को मिली 10 दिन की पिछली हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद शुक्रवार को सोयब को पटियाला हाउस अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई कवर करने के लिए मीडिया कर्मियों पर रोक लगी थी। आरोपी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने हिरासत की अवधि 10 दिन बढ़ा दी। एनआईए के एक अधिकारी प्रवक्ता ने कहा था कि एजेंसी ने दिल्ली आतंकवादी बम धमाके से पहले "आतंकवादी उमर-उन नबी" की मदद करने के आरोप में हरियाणा के फरीदाबाद के

धौज के निवासी सोयब को गिरफ्तार किया है। सोयब इस मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया सातवां आरोपी है। यह मामला "व्हाइट-कॉलर" आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़ा है, जिसका जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पर्दाफाश किया था। एनआईए ने पहले एक बयान में कहा था कि एजेंसी आत्मघाती बम धमाके से संबंधित विभिन्न सुराग तलाश रही है, और हमले में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए संबंधित पुलिस बलों के समन्वय से राज्यों में तलाशी अभियान चला रही है।

डीजीसीए ने साप्ताहिक विश्राम के नियम लिए वापस, पायलटों से सहयोग की अपील

इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए ने पायलटों के लिए उड़ान ड्यूटी मानदंडों में किया संशोधन

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी इंडिगो से जुड़ी दिक्कतों के बीच विमानन क्षेत्र के नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पायलटों के लिए छुट्टियों के स्थान पर साप्ताहिक विश्राम अवधि की अनुमति दी है। इसके साथ ही डीजीसीए ने कई विमानन कंपनियों को उड़ान शुल्क मानदंडों में संशोधन किया है। डीजीसीए के मुताबिक इस संकट की शुरुआत नई उड़ान ड्यूटी समय सीमाएं (एफडीटीएल) नियमों के लागू होने से हुई है, खासकर इंडिगो एयरलाइन में। इन नियमों के तहत अब पायलटों की ड्यूटी, उड़ान के घंटे, रात में लैंडिंग की संख्या और आराम की अवधि पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सख़्ती के साथ तय की गई है। नए नियमों में प्रमुख बदलाव किये गए

हैं, जिसमें पायलटों की साप्ताहिक छुट्टी 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई है। रात की परिभाषा अब 00:00–05:00 से बढ़ाकर 00:00–06:00 कर दी गई है। रात में लैंडिंग की सीमा सप्ताह में 6 से घटाकर 2 कर दी गई है। पायलट अब लगातार दो से अधिक रात ड्यूटी नहीं कर सकते। इससे पहले डीजीसीए ने पहले निर्देश जारी किए थे कि क्रू सदस्यों को साप्ताहिक विश्राम के बदले कोई भी अवकाश नहीं दिया जाएगा।

उड्डयन मंत्री ने एयरलाइन उड़ानें बाधित होने पर उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को इंडिगो एयरलाइन सहित कई एयरलाइन की उड़ानों में व्यापक रुकावट को लेकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना हो। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक महानिदेशालय नागरिक उड्डयन (डीजीसीए) की चार सदस्यीय जांच समिति में संयुक्त महानिदेशक संजय के. ब्रम्हणे, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, एसएफओआई कैप्ट. कपिल मंगलीक और एफओआई कैप्ट. लोकेश रांपाल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को हो रही भारी असुविधा को देखते हुए तत्काल और सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसमें यात्रियों के हित को सर्वोपरि रखा गया है। इससे जुड़ी समस्याओं को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक 24×7 कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जिसके लिए उन्होंने संपर्क नं 011-24610843, 011-24693963, 096503-91859 जारी किए हैं। इस जांच का उद्देश्य इंडिगो की उड़ानें प्रभावित होने की जांच करना, जवाबदेही तय करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाना है।

संक्षिप्त खबरें

महिला ने फांसी लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

नोएडा। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सदरपुर कॉलोनी में रहने वाली एक महिला ने गुरुवार रात को फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम भेजकर मामले की जांच कर रही है। थाना सेक्टर 39 के प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सदर कॉलोनी सेक्टर 45 में रहने वाले विकास की पत्नी शिवानी (19) ने फांसी लगा लगा ली। परिजनों ने उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को पोस्टमार्टम भेजकर आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है।

बैंक कर्मी ने युवती की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर किया वायरल

नोएडा। थाना सेक्टर 20 में एक युवती ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाया है कि उसने उसकी कुछ निजी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। इस मामले में युवती ने युवक के खिलाफ थाना में तहरीर भी दी है। पीड़ित महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक डीपी शुक्ल ने शुक्रवार को बताया कि निठारी गांव में रहने वाली एक युवती ने गुरुवार देर रात को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह एक कंपनी में काम करती है। दिल्ली निवासी सूरज सिंह जो की एक बैंक में काम करता था। वह कुछ दिन पहले उसकी कंपनी में काम करने वाले लोगों का खाता खुलवाने के लिए कंपनी में आया था। तभी से उसकी उससे जान पहचान हो गई। दोनों आपस में मिलते रहे। इसी दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और इस दौरान उसने उसकी कुछ निजी फोटो खींच ली थी। अब आरोपित उस पर शादी का दबाव बना रहा है। जब उसने मना किया तो इस बात से नाराज होकर उसने इंस्टाग्राम पर उसकी फर्जी आईडी बनाई और उन सभी निजी फोटो को वायरल कर दिया। इतना ही नही आरोपित ने उन सब फोटो को उसके होने वाले पति विनय और उसके पिता बलविंदर सिंह को उनके व्हाट्सएप पर भी भेज दी। आरोपित मौजूदा समय में सेक्टर 50 स्थित दूसरी बैंक में नौकरी कर रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि युवती की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बिजली के दो ट्रांसफार्मर चोरी, अवर अभियंता ने दर्ज कराई रिपोर्ट

नोएड। थाना बादलपुर क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर लगे दो बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी हो गए हैं। विद्युत विभाग के अवर अभियंता की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना बादलपुर के प्रभारी निरीक्षक अमित भड़ाना ने शुक्रवार को बताया कि बीती रात को विद्युत विभाग के अवर अभियंता सुरेंद्र कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि शिवा फिल्म सिटी ग्राम धूम मानिकपुर के पास लगे 63 किलो वाट के ट्रांसफार्मर तथा भारत गैस एजेंसी के पास लगे 250 किलो वाट के बिजली के ट्रांसफार्मर अज्ञात बदमाशों ने चोरी कर लिया है। उनके अनुसार बदमाशों ने ट्रांसफार्मर खोलकर ट्रांसफार्मर का तेल और उसके अंदर रखे हुए अन्य कीमती उपकरण चोरी कर लिया है। बदमाश ट्रांसफार्मर के लोहे के बॉक्स से को छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शिक्षकों का विवरण 15 तक पोर्टल पर डालना अनिवार्य

नोएडा। यूपी बोर्ड की 10वीं-12वीं की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित होने के बाद अब केंद्रों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बोर्ड ने 15 दिसंबर तक वेबसाइट पर शिक्षकों का विवरण डालने ने निर्देश दिए हैं। परिषद के सचिव ने कहा है कि विद्यालयों के प्रधानाचार्य उनके विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों का विवरण वेबसाइट पर समय से अपलोड कर दें। विवरण अपलोड करते समय एक बार पुनः पूर्ण सतर्कता और गहनता से जांच अवश्य की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में कोई शिक्षक गलत विषय में परीक्षक के रूप में न चुना जाए और न ही कोई अपात्र शिक्षक चयनित हो सकें। यदि कोई अयोग्य शिक्षक परीक्षक नियुक्त होता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य की होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि परिषद की वेबसाइट पर शिक्षकों के विवरण अपलोड एवं अपडेट करने की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक सक्रिय रहेगी।

शीतलहर और कोहरे की चुनौतियों पर जिला प्रशासन गंभीर, समीक्षा बैठक में बनाई गई व्यापक कार्य योजना

गौतम बुद्ध नगर। जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देशों के क्रम में डिप्टी कलेक्टर चारूल यादव की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के कार्यालय कक्ष में शीतलहर और घने कोहरे की संभावित परिस्थितियों को देखते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आमजन की सुरक्षा, राहत कार्यों की सुचारू व्यवस्था तथा आपातकालीन सेवाओं को पूर्ण क्षमता से संचालित करने हेतु समग्र कार्ययोजना पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक के अंत में यह भी निर्देशित किया गया कि संबंधित सभी अधिकारी अपनी-अपनी कार्ययोजना की विस्तृत रिपोर्ट 03 दिवस के भीतर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, ताकि आगामी कार्यवाही समयबद्ध और प्रभावी ढंग से संचालित की जा सके।

सड़कों की मरम्मत, गड्ढों की भराई, डिवाइडरों की पेंटिंग, रोड मार्किंग, रिफ्लेक्टर तथा निर्माणाधीन स्थलों पर सुरक्षा चिन्हांकन सहित सभी कार्य तत्काल पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रमुख सड़कों और मोहल्लों में स्थापित प्रकाश बिंदुओं की मरम्मत तथा उनके निर्धारित समय पर संचालन को भी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। यातायात विभाग को वाहनों पर नारंगी रंग के चेतावनी रेडियम स्टिकर लगाने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने, मास्क उपयोग तथा सड़क सुरक्षा नियमों के पालन हेतु जनजागरूकता अभियान को तेज करने और शीतलहर के दौरान किसी भी व्यक्ति को सड़क पर रात में सोता न मिलने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नगर निकायों और सम्बंधित अधिकारियों को अलाव की व्यवस्था, निराश्रित एवं गरीब व्यक्तियों को कंबल वितरण, तथा सभी रैन बसेरों में साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन, पेयजल, विद्युत, शौचालय, बिस्तर और कंबलों की 24×7 उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक रैन बसेरे पर नोडल अधिकारी तैनात कर उनकी सूचना कार्यालय को भेजने एवं आपदा प्रहरी ऐप पर अलाव और रैन बसेरों की दैनिक अपडेटिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। अग्निशमन विभाग को सभी उपकेन्द्रों को संसाधनों सहित 24×7 क्रियाशील रखने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आग से बचाव संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। पशुचिकित्सा विभाग को गौशालाओं में अलाव, दवाइयों, टीकाकरण और पशु सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही पशुओं में शीतलहरजनित बीमारियों की रोकथाम हेतु विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग को जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अस्पतालों में बेड आरक्षित रखने, दवाओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने, चिकित्सकों की उपलब्धता तथा एम्बुलेंस सेवाओं को पूरी क्षमता में रखने के निर्देश दिए गए।

श्रम विभाग को लेबर चौराहों का निरीक्षण कर श्रमिकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा जरूरतमंद श्रमिकों को कंबल वितरण कराने के निर्देश दिए गए। कोटेदारों को अपने क्षेत्रों में गरीब एवं असहाय लोगों की सूची तैयार कर संबंधित तहसीलदार के माध्यम से कंबल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सभी अधिकारियों को प्रतिदिन राहत पोर्टल पर कंबल वितरण, रैन बसेरों में ठहरे व्यक्तियों की संख्या और अलाव स्थलों की जानकारी नियमित रूप से फीड करने को भी कहा गया। आयोजित बैठक का सफल संचालन जिला आपदा विशेषज्ञ ओमकार चतुर्वेदी द्वारा किया गया। बैठक में जिला विकास अधिकारी शिव प्रताप परमेश, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ अरुण कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री राम बहादुर एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी पहुंचे सांसद महेश शर्मा के घर, पुष्प अर्पित कर उनकी मां को दी श्रद्धांजलि

नोएडा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार शाम 4 बजे के करीब गौतम बुद्ध नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा के सेक्टर 15 ए स्थित घर पर पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर महेश शर्मा की मां ललिता शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्जित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए उनके इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदना व्यक्त की। वह करीब 20 मिनट तक डॉक्टर महेश शर्मा के आवास पर रुके।

इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शुक्रवार एक बजे के करीब डॉक्टर महेश शर्मा के आवास पर पहुंचे। उन्होंने भी उनकी मां के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नितिन गडकरी करीब आधे घंटे तक डॉक्टर महेश शर्मा के आवास पर रुके। उन्होंने उनके आवास पर मौजूद लोगों से भी बातचीत की। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी, विप्लव देव, पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, रालोद के वरिष्ठ नेता के सी त्यागी, मंत्री एसपी सिंह बघेल सहित सैकड़ों की संख्या में देश के गणमान्य लोग, नेता, समाजसेवी, व्यापारी, किसान संगठनों के नेता, व्यापारी संगठनों के नेता और डॉक्टर सांसद महेश के आवास पर पहुंचे तथा उनकी मां के चित्र पर पुष्प पर अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विदित हो कि गौतम बुद्ध नगर के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ महेश शर्मा की मां ललिता शर्मा का बीते 26 नवंबर बुधवार को निधन हो गया था। उसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके आवास पर पहुंचे तथा उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सान्त्वना देते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उस दिन से आज तक उनके आवास पर देश के बड़े-बड़े नेताओं ,उद्यमियों ,व्यापारियों, समाजसेवी लोगों का आने-जाने का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही लोग उनकी मां को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके सेक्टर 15 ए स्थित आवास पर आने शुरू हो जाते हैं। यह सिलसिला देर रात तक चलता है।

SIR को लेकर विधायक ने की जेवर और जहांगीरपुर में बैठकें

गौतम बुद्ध नगर। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कस्बा जेवर तथा जहांगीरपुर में कस्बावासियों के साथ आयोजित बैठकों में एसआईआर से जुड़े सभी कार्यों की कस्बों के संभ्रांत नागरिक और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत समीक्षा की गई। इस मौके पर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के टिप्स दिए।

इस मौके पर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) साथियों का मनोबल बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनकी निष्ठा और मेहनत ही प्रत्येक मतदाता तक सही एवं समय पर जानकारी पहुंचाने का आधार है। इस प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने आगे कहा कि चुनाव आयोग की सभी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से वंचित न रहे। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण केवल प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि हम सब की भी जिम्मेदारी है।

बिल्डरों से साठगांठ कर प्रोफाइल फंडिंग करवाने वाले गैंग के 8 बदमाश गिरफ्तार

नोएडा। बिल्डरों के साथ सांठगांठ कर धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रोफाइल फंडिंग कराने तथा फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोन दिलवाने वाले गैंग के आठ लोगों को उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ थाना सूरजपुर में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ (नोएडा यूनिट) राजकुमार मिश्रा ने बताया कि एक सूचना के आधार पर निरीक्षक सचिन कुमार और उनकी टीम ने आज रामकुमार, नितिन जैन, मोहम्मद वसी, शमशाद आलम, इंद्र कुमार कर्मकार, अनुज यादव, अशोक कुमार उर्फ दीपक जैन उर्फ रिंकी, ताहिर हुसैन सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि इनके पास से एसटीएफ ने 126 पासबुक, 170 डेबिट कार्ड, 45 आधार ,कार्ड 27 पैन कार्ड, 15 आईडी कार्ड, निर्वाचन आयोग के पांच पहचान पत्र, 26 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, तीन कारें, विभिन्न व्यक्तियों के होम लोन, पर्सनल लोन से संबंधित दस्तावेज तथा घरों की रजिस्ट्रियां बरामद की है। इनके 220 बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिली है, जिन्हें फ्रिज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये पूछताछ के दौरान पता चला है कि यह बदमाश कूटरचित दस्तावेज को बनाकर फेक नाम से कई बैंकों से धोखाधड़ी से फ्लैट और मकान पर होम लोन करवा रहे थे।

उसके बाद ये लोग गायब हो जाते थे। यह गैंग फर्जी प्रोफाइल बनाकर चंडीगढ़ ,उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों के बिल्डरों के सांठगांठ करके बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से प्रोफाइल फंडिंग भी कर रहे थे। अब तक की जांच में करीब 10 बैंकों से 100 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का पता चला है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है।

एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति गंभीर

नोएडा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में शुक्रवार की सुबह एक्यूआई खतरनाक स्तर के पास बना रहा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लाइव डेटा के अनुसार अधिकांश स्टेशनों पर एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि कई स्थानों पर यह 350–380 की 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक्यूआई 292, वसुंधरा में 295 और संजय नगर में यह बढ़कर 301 दर्ज किया गया। वहीं, लोनी जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही और यहां एक्यूआई 380 तक पहुंच गया, जो अत्यधिक प्रदूषण की स्थिति को दर्शाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह स्तर सांस से संबंधित बीमारियों, एलर्जी, आंखों में जलन और लंबे समय के लिए फेफड़ों पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।

नोएडा में भी स्थिति सामान्य नहीं है। सेक्टर-125 में एक्यूआई 367 जबकि सेक्टर-116 में 347 तक पहुंच चुका है। वहीं सेक्टर-62 में एक्यूआई 286 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। समूचे नोएडा क्षेत्र में वायु गुणवत्ता लगातार सामान्य से खराब स्तर पर दर्ज की जा रही है और इसमें सुधार के कोई संकेत नहीं मिल रहे। दिल्ली में हालात और भी अधिक बिगड़े हुए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक है। अलीपुर में एक्यूआई 324, आनंद विहार में 347, अशोक विहार में 340, बवाना में 373, बुराड़ी क्रॉसिंग में 326, चांदनी चौक में 347 और डी टी यू परिसर में 345 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज के आसपास भी एक्यूआई 343 रिकॉर्ड किया गया, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक माना जाता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इतनी खराब गुणवत्ता वाली हवा लंबे समय तक शरीर में घातक प्रभाव छोड़ सकती है।

मौसम विभाग का कहना है कि इस बार सर्द हवा चलने के बावजूद प्रदूषण में उल्लेखनीय गिरावट नहीं देखी गई है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इससे प्रदूषण में सुधार की संभावना कम है। जिला प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक बाहर न निकलने, मास्क पहनने और घरों में एयर प्यूरीफायर का उपयोग करने की सलाह दी है। साथ ही निर्माण कार्यों पर निगरानी बढ़ाई गई है और सड़क पर धूल नियंत्रण के लिए छिड़काव किया जा रहा है। एनसीआर में फिलहाल प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक है और स्थिति फिलहाल सुधरती नहीं दिख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मौसम में बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में एक्यूआई और भी बढ़ सकता है।

मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग में नवनिर्मित नालियों और सड़कों का किया उद्घाटन

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ब्लॉकों में नवनिर्मित नालियों और सड़कों का उद्घाटन किया। उन्होंने इसके साथ ही विकास कार्यों का स्थल पर जाकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि शालीमार बाग में अटल कैंटीन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, नए सार्वजनिक शौचालय, नए पार्क, वॉटर एटीएम सहित आधारभूत नागरिक सुविधाओं पर कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये योजनाएं गरीब, मध्यम वर्ग और हर परिवार के जीवन में सम्मान, सुविधा और सुरक्षा जोड़ने का प्रभावी माध्यम हैं। शालीमार बाग को स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं की सुगमता, सुचारु सड़क नेटवर्क और मजबूत शहरी व्यवस्थाओं के साथ एक आदर्श मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित किया जाए। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी और स्थानीय निवासी मौजूद रहे।

प्रदूषण से निपटने को रेखा गुप्ता सरकार के लगातार प्रयासः रीना महेश्वरी

अशोक नगर वार्ड की निगम पार्षद रीना महेश्वरी ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि हर साल सर्दियों में यह गंभीर रूप ले लेता है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों ने प्रदूषण रोकने के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला, जिसके कारण स्थिति और खराब हुई। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार ने 11 वर्षों में कोई ठोस योजना नहीं बनाई, जिससे समस्या और विकराल हो गई। रीना महेश्वरी के अनुसार रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार प्रदूषण को लेकर बेहद गंभीर है और ट्रिपल इंजन सरकार ने कई प्रभावी योजनाएँ लागू की हैं। कृत्रिम बारिश जैसी पहल भी की गई, हालांकि मौसम ने अपेक्षित साथ नहीं दिया। इसके बावजूद सरकार गड्ढे भरने, धूल नियंत्रण, प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कार्रवाई और सड़कों पर नियमित छिड़काव जैसे कदम तेजी से उठा रही है। एक महीने में हजारों चालान जारी किए जा चुके हैं। रीना महेश्वरी ने बताया कि दिल्ली की हवा लगातार खराब बनी हुई है, विशेष रूप से सर्दियों में AQI बेहद गिर जाता है। इसी को देखते हुए सरकार अब मिस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद ने आईटीओ के पास लगाई गई मिस्ट टेक्नोलॉजी का निरीक्षण भी किया। आईटीओ के डिवाइडर पर 19 स्थानों पर मिस्ट स्प्रे लगाए गए हैं और जल्द ही 16 और लगाए जाएंगे। ये स्प्रे ट्रैफिक के पीक समय में 10-10 मिनट के अंतराल पर चलते हैं और एक ड्रिपिंग प्लांट से जुड़े होते हैं। यदि यह तकनीक सफल रही, तो दिल्ली के 9 प्रमुख हॉटस्पॉट के मुख्य मार्गों पर 305 और मिस्ट स्प्रे लगाए जाएंगे।

सड़क-फ्लाईओवर की स्वच्छता-सुंदरता निजी कंपनी संभालेगी

पीडब्ल्यूडी और जीएमआर के बीच आजादपुर मार्केट से इंद्रलोक तक सड़क सौंदर्यीकरण को लेकर समझौता

नई दिल्ली। दिल्ली में फ्लाईओवर एवं सड़कों की देखरेख का काम पीडब्ल्यूडी ने निजी कंपनियों को सौंपा है। यह कंपनियां न केवल उस जगह की देखरेख करेंगी बल्कि वहां की सुंदरता बढ़ाने का भी काम करेगी। शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने जीएमआर कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

पीडब्ल्यूडी द्वारा जीएमआर को आजादपुर मंडी से इंद्रलोक तक की सड़क के रखरखाव, सफाई एवं पैधारोपण का काम तीन वर्ष तक के लिए दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली में सड़कों को स्वच्छ एवं उसके आसपास को सुंदर बनाने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली सरकार शहर में सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए कई सड़कों व फ्लाईओवरों को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), वेदांता, जीएमआर आदि प्रमुख कंपनियों को सौंप रही है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार और जीएमआर के बीच शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन पर

हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत जीएमआर कंपनी आजाद पुर मंडी से इंद्रलोक तक सड़क के रखरखाव, सफाई और पौधरोपण का काम तीन साल तक संभालेगी। पौधारोपण, सफाई और अन्य कार्यों पर खर्च जीएमआर द्वारा स्वयं किया जाएगा। उनके द्वारा एक सौर पंप भी लगाया जाएगा। रेखा गुप्ता ने बताया कि चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, पंचशील क्लब फ्लाईओवर, आईआईटी फ्लाईओवर, पंजाबी बाग व अरविंदो मार्ग के लिए आईओसीएल और मुकरबा चौक से मधुबन चौक तक कार्य एक अन्य कंपनी को आवंटित किया गया है।

उन्होंने कहा कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई में दिल्ली की बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत आईजीएल (इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड) मुनिरका फ्लाईओवर का काम संभालेगा, वेदांता को पंजाबी बाग फ्लाईओवर (राम मंदिर की तरफ), आउटर रिंग रोड (शालीमार बाग की तरफ) और राव तुला राम रोड फ्लाईओवर का काम सौंपा गया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि नेताजी सुभाष पैलेस फ्लाईओवर के रखरखाव की जिम्मेदारी गोदरेज कंपनी संभालेगी। मुख्यमंत्री ने की जनता से सहयोग की अपील इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता से प्रदूषण कम करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग कार पूलिंग कर, लकड़ी-कोयला-बायोमास आदि नहीं जलाकर और स्वच्छता बनाकर प्रदूषण को कम करने में सहयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही कंपनियां कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देकर भी प्रदूषण कम करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि दिल्ली में स्वच्छता को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है।

इग्नू की वीसी प्रो. उमा कांजीलाल को मिला प्रो. जी. राम रेड्डी अवॉर्ड 2025

नई दिल्ली। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) ने घोषणा की है कि उसकी वाइस-चांसलर प्रो. उमा कांजीलाल को वर्ष 2025 के लिए डिस्टेंस एजुकेशन में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रतिष्ठित प्रो. जी. राम रेड्डी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान 4 दिसंबर 2025 को डॉ. बी. आर. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर प्रो. घंटा चक्रपाणि द्वारा प्रदान किया गया, जिस दिन महान शिक्षाविद और भारत में डिस्टेंस एजुकेशन के अग्रणी प्रो. जी. राम रेड्डी की जयंती भी मनाई गई। यह पुरस्कार ओपन और डिस्टेंस लर्निंग में प्रो. कांजीलाल के उल्लेखनीय योगदान, टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने में उनके प्रभावी नेतृत्व और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच विस्तार की प्रतिबद्धता को सम्मानित करता है। इसी अवसर पर बीआरएओयू और प्रो. जी. राम रेड्डी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वार्षिक प्रो. जी. राम रेड्डी मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया, जिसमें भारत में ओपन यूनिवर्सिटी मॉडल की नींव रखने वाले इस महान शिक्षाविद को श्रद्धांजलि दी गई। प्रो. जी. राम रेड्डी को भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी—डॉ. बी. आर. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी—की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और बाद में इग्नू के प्रथम वाइस-चांसलर के रूप में लाखों शिक्षार्थियों को लचीली और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने वाले सिस्टम के निर्माण के लिए जाना जाता है। इग्नू ने प्रो. उमा कांजीलाल को इस सम्मान के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह पुरस्कार यूनिवर्सिटी के शिक्षा में नवाचार, समावेशिता और उत्कृष्टता के निरंतर प्रयासों का प्रतीक है।

संक्षिप्त खबरें

दिल्ली में तमिलनाडु पुलिस की बस से भिड़ी कार, दोनों वाहनों में लगी आग

नई दिल्ली। दिल्ली के पश्चिमी जिले के हरि नगर स्थित दिल्ली हाट के समीप शुक्रवार सुबह तमिलनाडु पुलिस की एक बस और एक कार टकराने के बाद आग की चपेट में आ गईं। हादसे में दोनों वाहन पूरी तरह जल गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। पुलिस अधिकारी के अनुसार, पूर्वाह्न करीब 11:38 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल मिली कि सड़क पर एक बस में आग लग गई है। हरि नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पाया गया कि तमिलनाडु पुलिस की बस और उसके पीछे चल रही बलेनो कार दुर्घटनाग्रस्त हालत में खड़ी थीं और दोनों वाहन पूरी तरह जल चुके थे। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बलेनो कार ने पीछे से बस को टक्कर मारी, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। दुर्घटना के समय किसी के घायल होने या किसी प्रकार की मौत की सूचना नहीं है। मौके पर फॉरेंसिक टीम और क्राइम टीम को जांच के लिए बुला लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी।

एनडीएमसी आज एनडीसीसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित करेगी सुविधा शिविर

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) 6 दिसंबर, शनिवार को एनडीसीसी कन्वेंशन सेंटर, जय सिंह रोड (पालिका केंद्र के पास) में अपना सुविधा शिविर आयोजित करेगी। यह शिविर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। यह कार्यक्रम एनडीएमसी की नागरिक आउटरीच पहल का हिस्सा है, जिसके तहत नागरिकों को विभिन्न नगरपालिका सेवाओं से संबंधित जानकारी, सुविधा और शिकायत निवारण एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाता है। सुविधा शिविर में एनडीएमसी क्षेत्र के निवासी, सेवा उपयोगकर्ता, आरडब्ल्यूए, एमटीए, तथा सेवारत और सेवानिवृत्त एनडीएमसी कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया है। वे बिजली कनेक्शन (नया, लोड परिवर्तन, नाम परिवर्तन), संपत्ति कर, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, कर्मचारियों के सेवा मामले, जलभराव, स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान, सड़क मरम्मत, पेंशन योजनाएँ तथा बारात घरों व पार्कों की बुकिंग जैसी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। विभिन्न विभागों के हेल्पडेस्क नागरिकों की सीधे और त्वरित सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। पालिका परिषद हर महीने के पहले शनिवार को ऐसा शिविर आयोजित करती है ताकि पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक-अनुकूल प्रशासन को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके साथ ही एनडीएमसी "जन सुविधा पोर्टल" भी संचालित कर रही है, जिसके माध्यम से नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उनकी स्थिति देख सकते हैं और समाधान पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

हत्या की गुत्थी सुलझी, तीन नाबालिग समेत चार को पकड़ा

नई दिल्ली। दक्षिण पूर्वी जिले के हजरत निजामुद्दीन इलाके में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन नाबालिग समेत चार लोगों को पकड़ा है। युवक का शव बरापुला फ्लाईओवर के नीचे मिला था। पुलिस ने मृतक की कार, खून लगे कपड़े और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है।

दक्षिण पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि तीन दिसंबर की सुबह पीसीआर को कॉल मिली कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास बरापुला फ्लाईओवर के नीचे एक युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में मृतक की पहचान कुलदीप उर्फ राम सिंह (27) के रूप में हुई। कुलदीप मूलतः जोरियाम गांव जिला अयोध्या (उप्र) के रहने वाले थे। उक्त ममले में हजरत निजामुद्दीन थाना

पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले की स्पेशल स्टाफ, एसटीएफ, नार्कोटिक्स स्क्वाड और चौकी सराय काले खां की संयुक्त टीम को लगाया गया। टीम ने आस-पास के 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसी दौरान भोगल स्थित जैन मंदिर के पास बने एक शौचालय का सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा। जिसमें मृतक के साथ झगड़ा करते चार संदिग्ध दिखे।

फुटेज व तकनीकी निगरानी के बाद आरोपितों की पहचान हुई। इसके बाद मुख्य आरोपित इमरान उर्फ पानवाड़ी (19) व उसके तीन नाबालिग को दबोचा गया। जांच में पता चला कि इमरान पहले भी झपटमारी व चोरी के तीन मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पूछताछ में आरोपितों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोपितों ने बताया कि जन्मदिन मनाने के बाद चारों इंडिया गेट की ओर जा रहे थे। उसी दौरान भोगल के पास बने शौचालय के बाहर उनकी कार के साथ मृतक की कहासुनी हो गई। आरोपितों ने गुस्से और नशे में मृतक पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी और उसकी कार लेकर फरार हो गए।

अक्षय ईआर के नक्सल कनेक्शन का वीडियो हमारे पास : दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली। इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के नाम पर हुए प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस की जांच ने गंभीर मोड़ ले लिया है। पुलिस का दावा है कि पुलिसकर्मियों पर मिर्ची स्प्रे से हमला करने वाले प्रदर्शनकारी अक्षय ईआर के नक्सली संबंध सामने आए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता भी यही अक्षय है। पुलिस जांच रिपोर्ट में कहा गया है, "उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। फोन की सर्च हिस्ट्री में नक्सलियों से जुड़े वीडियो और लिंक मिले हैं।" पुलिस सूत्र ने बताया कि फोन की पड़ताल से पता चला कि अक्षय का नक्सलियों से संबंध है। पुलिस के अनुसार, भगत सिंह छात्र एकता मंच (बीएससीईएम) नामक संगठन ने इस प्रदर्शन में बड़ी भूमिका निभाई। अक्षय इस समूह का प्रमुख व्यक्ति है, जबकि गुरकीरत इसकी अध्यक्ष है और उसकी बहन रवजोत समूह की एडमिन है। पुलिस जांच में सामने आया है, "अक्षय मुख्य साजिशकर्ता है। उसके फोन की सर्च हिस्ट्री में नक्सलियों से जुड़े वीडियो और लिंक मिले हैं।

फोन पर गुरकीरत द्वारा भेजा गया एक टेक्स्ट मैसेज भी है जिसमें माडवी हिडमा को 'हीरो' बताया गया है, न कि नक्सली।" प्रदर्शन के दौरान अक्षय की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें पुलिस उसे दबोचकर जमीन पर पटक रही थी। पुलिस का कहना है कि मिर्ची स्प्रे छीनने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। अक्षय ने कथित तौर पर कॉन्स्टेबल इशांत की आंखों में मिर्ची स्प्रे छिड़का था और उसके पास से एक मिर्ची स्प्रे की बोतल बरामद हुई थी। पुलिस का दावा है कि दूसरी आरोपी गुरकीरत, भगत सिंह छात्र एकता मंच की अध्यक्ष है। पुलिस ने कहा, "वायु प्रदूषण के नाम पर बुलाए गए इस प्रदर्शन में मारे गए नक्सली माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाने की पूरी तैयारी और एजेंडा था।" पुलिस ने यह भी दावा किया है कि एक अन्य आरोपी क्रांति उर्फ प्रियांशु सिंह ने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया और जांच को गुमराह कर रहा है। इसके अलावा, एक अन्य आरोपी विष्णु तिवारी के फोन से 22 नवंबर को लिया गया स्क्रीनशॉट मिला है जिसमें हिडमा को सरेंडर के बहाने मारा गया, यह झूठी जानकारी फैलाई जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने कुल 23 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की हैं। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

दिल्ली में मोबाइल स्नैचर्स गैंग का भंडाफोड़, 103 मोबाइल बरामद

नई दिल्ली। उत्तर पश्चिम जिले के अशोक विहार थाना पुलिस ने एक झपटमार व रिसीवर को गिरफ्तार किया है। आरोपित झपटमारी के फोन अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए नेपाल भी भेजता था। गैंग के दो मुख्य आरोपित किशन उर्फ किशोर उर्फ गोलू और मोहित उर्फ बादशाह के साथ दो अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 103 चोरी/छीने गए मोबाइल फोन, एक देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है।

उत्तर पश्चिमी जिले के पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने शुक्रवार को बताया कि एक दिसंबर को फैक्ट्री में गार्ड का काम कर रहे गणेश दुबे का मोबाइल दो बदमाशों ने ब्लैक पल्सर बाइक पर आकर छीन लिया। शिकायत मिलते ही अशोक विहार थाने की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने पहले आरोपित किशन उर्फ गोलू को दबोचा। उसके कब्जे से देशी कट्टा, कारतूस और झपटा हुआ फोन बरामद हुआ। किशन के घर की तलाशी में 40 और मोबाइल फोन मिले। बाइक भी चोरी की निकली, जो कि केशवपुरम थाना क्षेत्र से गायब थी। इसके बाद किशन की निशानदेही पर पुलिस ने चार दिसंबर को उसके साथी मोहित उर्फ बादशाह को गिरफ्तार

किया। मोहित के पास से भी एक चोरी का मोबाइल मिला। पूछताछ में पता चला कि दोनों फोन रोहित और अमित नामक रिसीवर को सप्लाई करते थे। उसी दिन पुलिस ने रोहित को भी दबोच लिया। उसकी और अमित की झुग्गी से 61 मोबाइल बरामद हुए।

आरोपित पैदल चल रहे लोगों, मजदूरों व फैक्ट्री कर्मियों को निशाना बनाते थे। पुलिस की आंख में धूल झोंकने लिए चोरी की बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाते थे। जांच में पता चला है कि चोरी किए गए मोबाइल में अक्सर मिलने वाले आसान पैटर्न/पिन—जैसे सीधी लाइन, L, Z, M, N शेप या 1234 जैसे नंबर का अंदाजा लगाकर फोन अनलॉक करते। अनलॉक होने पर यूपीआई, ई-वॉलेट,एसएमएस, बैंकिंग ऐप्स और ईमेल तक पहुंचकर लाखों के अनधिकृत लेनदेन कर डालते। बाद में मोबाइल को रोहित-अमित जैसे रिसीवर को देते, जहां से यह फोन नेपाल भेजे जाते थे। नेपाल में आईएमईआई बदलने व फ्लैशिंग के बाद इन्हें बेचा जाता था।

रूस की एच एस ई यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर डीयू बनाएगा स्पेस मिरर लैब

एकेडमिक रिसर्च के लिए स्पेस स्पेक्ट्रम में डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन पर होगा कामः प्रो. योगेश सिंह

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय और रूस की एच एस ई यूनिवर्सिटी मिलकर स्पेस मिरर लैब स्थापित करेंगे। इस विषय को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय और नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी हायर स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स (एच एस ई यूनिवर्सिटी), रूस के बीच 'स्टेटमेंट ऑफ़ कोऑपरेशन' पर शुक्रवार, 5 दिसंबर को हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि यह बहुत ही खुशी का विषय है दो मित्र देशों के दो बड़े संस्थान संयुक्त रूप से अनुसंधान में आगे आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित सहयोग एच एस ई यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर दिल्ली विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में एक स्पेस मिरर लैब बनाने के लिए है। कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि एकेडमिक रिसर्च के मकसद से स्पेस स्पेक्ट्रम में डेटा स्टोरेज,

प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन पर दिल्ली विश्वविद्यालय और एचएसई यूनिवर्सिटी के बीच एक साइंटिफिक मिरर लैबोरेटरी बनाना बहुत ही दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी योजना है। इस सामूहिक कार्य के तहत, दोनों यूनिवर्सिटी मिरर लैब के ज़रिए मिलकर ऐसे जॉइंट रिसर्च और एजुकेशनल प्रोजेक्ट पर काम करेंगी जो भारत और रूस के लिए काम के होंगे। कुलपति ने कहा कि इसके अलावा भी कई और शैक्षणिक परियोजनाएं भी पाइपलाइन में हैं। उन्होंने कहा कि इन सांझा अकादमिक और अनुसंधान कार्यक्रमों से दोनों विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को भारी लाभ होगा। इस अवसर पर एच एस ई यूनिवर्सिटी के रेक्टर डॉ. निकिता अनिसिमोवा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता ने कुलपति प्रो. योगेश सिंह की मौजूदगी में स्टेटमेंट ऑफ़ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान रूस की ओर से एचएसई यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. मनोज शर्मा एवं उनके साथ सुश्री अनास्तासिया सर्गेवा उपस्थित रही, जबकि डीयू की ओर से डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो. बलराम पाणी, एसओएल की डायरेक्टर प्रो. पायल मागो, चेयरमैन इंटरनेशनल रिलेशन प्रो. नीरा अग्निमित्रा, डीन इंटरनेशनल रिलेशन प्रो. अनिल राय तथा प्रो. शैलेंद्र गोयल, चेयरमैन क्लचर काउंसिल एवं पीआरओ अनूप लाठर, फ़ैकल्टी ऑफ टेक्नोलोजी के डीन प्रो. संजीव सिंह तथा डीन अकादमिक प्रो. के. रत्नाबली सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

संपादकीय

जीडीपी माप अपडेट

केंद्र ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की नई श्रृंखला शुरू करने के लिए चर्चा पत्र पेश किया है। मकसद फरवरी 2026 से जीडीपी मापने के नए फॉर्मूले को लागू करना है। चर्चा पत्र से संकेत मिले हैं कि सरकार नए फॉर्मूले में किन पहलुओं को जगह देना चाहती है। इसके मुताबिक नई सीरीज़ का आधार वर्ष 2022-23 को बनाया जाएगा। इस तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद जो नया आधार वर्ष अपनाया था, वह लगभग एक दशक और आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा सरकार का इरादा जीडीपी माप में सक्रिय कंपनियों की नई परिभाषा, एलएलपी कंपनियों के आंकड़ों का अधिक विस्तृत रूप शामिल करना, कॉरपोरेट्स की सालाना रिपोर्ट्स से अधिक सूचनाएं लेना और गैर-निगमीकृत कंपनियों के सालाना सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को शामिल करना है।

साथ ही प्राइवेट कंपनियों, एमएसएमई दायरे में आने वाली अपेक्षाकृत बड़ी गतिविधियों, और कृषि क्षेत्र में इनपुट-आउटपुट अनुपात के मद्देनजर मूल्य-वर्धन (वैल्यू ऐड) की गणना करना है। जीडीपी में मुद्रास्फीति के प्रभाव की गणना की विधि में बड़े परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत स्थिर मूल्य पर सकल इनपुट और आउटपुट से अलग-अलग मुद्रास्फीति दर को घटाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे वैल्यू ऐडेड ग्रोथ की अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। सामान्य नजरिए से देखें, तो गुजरते समय और बदलते हालात के साथ जीडीपी जैसे आंकड़ों की माप को अपडेट करना स्वागतयोग्य प्रयास माना जाएगा।

लेकिन हालिया वर्षों में रहे अनुभव को ध्यान में रखें, तो इस आशंका में भी दम है कि यह सारा प्रयास बिना जमीनी हालत बदले बेहतर सूरत दिखाने का प्रयास ना बन जाए। विकास के पैमानों का मकसद हकीकत को समझना होना चाहिए, ताकि जहां कमजोरियां सामने आएं, उन्हें दूर करने की योजनाबद्ध कोशिश की जाए। जबकि सुधार का बिना इरादा रखे आंकड़ों की बाजीगरी अंततः यथार्थ को ढकने की कोशिश बन जाती है। बेहतर होगा, केंद्र ऐसे मोह में ना पड़े। प्रयास यह होना चाहिए कि जीडीपी की गणना और आम जन के जीवन स्तर में अधिकतम संबंध बने, ताकि नई जीडीपी सीरीज़ वास्तव में भारत की आर्थिक स्थिति का आईना बन सके।

जीएसटी सुधार से हुआ चमत्कार

भारतीय अर्थ व्यवस्था के लिये वित्त वर्ष-2025-26 की दूसरी तिमाही खुशी लेकर आई। जीडीपी आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मिले-जुले एवं उत्साहवर्धक संकेत लेकर आए हैं। भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में जीडीपी 5.6 प्रतिशत थी। दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े बीती छः तिमाहियों में सर्वाधिक हैं। नए आंकड़ों में वाणिज्यिक वाहनों और कृषि क्षेत्र में तेजी की बात कही गई है, वहीं निजी कारों की सुस्त बिक्री ने मध्यम वर्ग की चुनौतियों को भी उजागर किया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी किये गये ताजा आंकड़ों में रोचकता दिखाई दे रही है। वाणिज्यिक वाहनों की बढ़ती आवाजाही और निर्माण क्षेत्र में आई तेजी ने औद्योगिक गतिविधियों को नई गति प्रदान की है, वहीं निजी कारों की घटती बिक्री ने मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति पर सवाल कर दिए हैं, जिससे बेहतर आंकड़ों के बावजूद मध्यम वर्ग के लिए अभी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं।

-बीपी गौतम-

भारत की जीडीपी ग्रोथ ने अर्थशास्त्रियों को भी स्तब्ध कर दिया है। जीडीपी ग्रोथ के पीछे कई कारण हैं पर, सबसे बड़ा कारण जीएसटी में किया गया सुधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के चलते जीएसटी सुधार से ही चमत्कार हुआ है। देश के अंदर उत्पादन बढ़ा है पर, जीडीपी ग्रोथ को बनाये रखने के लिये उपभोग भी बढ़ाना होगा। मध्यम वर्ग अभी आशंकित है, वह पूंजी को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है, इसलिए मध्यम वर्ग का विश्वास जीतना होगा। आरबीआई को मध्यम वर्ग के लिए राहत देनी होगी, वहीं डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर होता दिख रहा है। हालांकि देश के अंदर रूपये को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं है। आम नागरिक भी समझ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की हठधर्मिता से हालात बिगड़ रहे हैं लेकिन, सरकार को स्वाभिमान की रक्षा करते हुये अमेरिका के साथ भी व्यापारिक रिश्ते सहज करने होंगे। सितंबर में समाप्त हुए भारत की दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं, इस दौरान 8.2 फीसदी जीडीपी ग्रोथ रही है, जो गत छः तिमाहियों में सबसे अधिक है, यह ग्रोथ उम्मीदों से कहीं अधिक है, इसने अर्थशास्त्रियों को भी स्तब्ध कर दिया है। मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और खपत ने जीडीपी उछाल में अहम भूमिका निभाई है। गत वित्त वर्ष-2024-25 की इसी तिमाही में यह ग्रोथ 5.6 फीसदी थी, वहीं चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में यह 7.8 फीसदी थी, जो पांच तिमाहियों का सबसे ऊंचा स्तर था। भारतीय रिजर्व बैंक के 7 फीसदी के अनुमान से भी यह ग्रोथ काफी अधिक है। नॉमिनल जीडीपी यानी, महंगाई को एडजस्ट किए बिना आर्थिक वृद्धि इस तिमाही में 8.7 फीसदी रही। ध्यान देने वाली विशेष बात है कि पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ तीन तिमाहियों के निचले स्तर 8.8 फीसदी पर आ गई थी।

जीडीपी के मजबूत आंकड़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुये शुक्रवार को कहा कि 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर लोगों की कड़ी मेहनत और उद्यम को दर्शाती है। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर बहुत उत्साहजनक है। यह हमारी विकास-समर्थक नीतियों और सुधारों के प्रभाव को दर्शाती है। यह हमारे लोगों की कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता को भी दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी और प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन की सुगमता को मजबूत करेगी।

जानकारों का कहना है जीडीपी में उछाल त्योहारों से पहले बढ़ी खपत और हाल में लागू जीएसटी सुधारों से संभव हुआ है, जिसने बाजार में अतिरिक्त मांग पैदा की और आर्थिक गतिविधियों को गति दी, यह विस्तार चीन के 4.8 प्रतिशत से अधिक रहा, यह उच्च सार्वजनिक निवेश, सेवाओं की मांग, औद्योगिक उत्पादन और फर्म उपभोग के अलावा निम्न आधार के सांख्यिकीय प्रभावों के कारण हुआ है, क्योंकि गत वित्त वर्ष की इसी तिमाही में अर्थव्यवस्था औसत से कम 5.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी। विनिर्माण उत्पादन में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछली तिमाही में यह 7.7 प्रतिशत और पिछले वर्ष की समान तिमाही में 7.6 प्रतिशत थी, वहीं निर्माण क्षेत्र में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछली तिमाही में यह 7.6 प्रतिशत थी।

भारतीय अर्थ व्यवस्था के लिये वित्त वर्ष-2025-26 की दूसरी तिमाही खुशी लेकर आई। जीडीपी आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मिले-जुले एवं उत्साहवर्धक संकेत लेकर आए हैं। भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में जीडीपी 5.6 प्रतिशत थी। दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े बीती छः तिमाहियों में सर्वाधिक हैं। नए आंकड़ों में वाणिज्यिक वाहनों और कृषि क्षेत्र में तेजी की बात कही गई है, वहीं निजी कारों की सुस्त बिक्री ने मध्यम वर्ग की चुनौतियों को भी उजागर किया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी किये गये ताजा आंकड़ों में रोचकता दिखाई दे रही है। वाणिज्यिक वाहनों की बढ़ती आवाजाही और निर्माण क्षेत्र में आई तेजी ने औद्योगिक गतिविधियों को नई गति प्रदान की है, वहीं निजी कारों की घटती बिक्री ने मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति पर सवाल कर दिए हैं, जिससे बेहतर आंकड़ों के बावजूद मध्यम वर्ग के लिए अभी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं।

अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी राहत लॉजिस्टिक्स सेक्टर से मिली है। वाणिज्यिक वाहनों को आर्थिक गतिविधियों का बैरोमीटर माना जाता है, इनकी बिक्री बढ़ी है। पिछले साल समान तिमाही में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 10.7 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई थी लेकिन, इस वर्ष 8.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। ट्रक और लोडर आदि की बिक्री बढ़ने से माना जाता है कि फैक्ट्रियों से माल की ढुलाई बढ़ी है, जो औद्योगिक उत्पादन में तेजी और रोजगार के नए अवसरों का संकेत है, यह टर्नअराउंड बताता है कि सुस्ती का दौर समाप्त हो रहा है। जीडीपी के आंकड़ों के अनुसार देश में वाणिज्यिक गाड़ियों की मांग बढ़ रही हैं, वहीं मध्यम वर्ग की ओर से खरीदी जाने वाली निजी कारों की बिक्री की गति कम हो गई है। निजी वाहनों की बिक्री वृद्धि दर घटकर 5.9 फीसदी रह गई है, जो पिछले वर्ष 9.9 फीसदी थी, इससे स्पष्ट है कि मध्यम वर्ग अभी भी महंगाई और ऊंचे ब्याज दरों के दबाव में है। लोग अपनी जमा पूंजी बचाने को प्राथमिकता दे रहे हैं और कार जैसी बड़ी खरीदारी से बच रहे हैं, इसीलिए त्योहारों और शादियों के बहाने कंपनियों को भारी डिस्काउंट का सहारा लेना पड़ता है।

आंकड़े सामने से खुशी देने वाले दिखाई दे रहे हैं लेकिन, आंशिक तौर पर आंकड़े विरोधाभासी भी दिख रहे हैं। एक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था का सप्लाई साइड, जैसे उत्पादन, निर्माण और लॉजिस्टिक्स मजबूती के साथ दौड़ रहा है और औद्योगिक गतिविधियों में ऊर्जा भर रहा है, वहीं दूसरी ओर डिमांड साइड अभी भी कमजोर दिखाई दे रही है अर्थात, उत्पादन के अनुरूप मांग नहीं बढ़ रही है। शहरी क्षेत्र का मध्यम वर्ग बड़ा उपभोक्ता है लेकिन, वह अभी महंगाई और उच्च ब्याज दरों के दबाव में खर्च करने से बच रहा है, इसके विश्वास को जागृत करना बड़ा कार्य करना शेष है, इस वर्ग के अंदर सरकार के कार्य करने के तरीके से ही विश्वास जागृत होगा।

अपना बनाने वालों, खरीदारों, डेवलपर्स और रियल एस्टेट निवेशकों के लिए बाजार में गर्माहट आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग सेक्टर में भारी मांग देखी जा रही है। सीमेंट उत्पादन में 7.3 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष 3.2 फीसदी थी, वहीं स्टील की खपत 8.8 फीसदी की दर से बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण सरकार की आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्र की आवास योजनाओं में आई तेजी है, जिससे इसका सीधा श्रेय सरकार को ही जायेगा। हालांकि मांग में इतनी तेज वृद्धि का असर कीमतों पर पड़ सकता है। घर बनाने की योजना बना रहे लोगों को अपने बजट में 5-10 फीसदी का अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनियां आवश्यक उत्पादों की कीमतें बढ़ाकर इसका भार आम उपभोक्ताओं पर डाल सकती हैं। आम आदमी की चिताओं में रसोई का बजट प्रमुख है। आम आदमी के लिए कृषि क्षेत्र से एक राहत भरी खबर है। चावल के उत्पादन की वृद्धि दर बढ़कर 2.9 फीसदी हो गई है, जो पिछले वर्ष मात्र 1.1 फीसदी थी, इसका सीधा लाभ आम आदमी को ही मिलेगा।

लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संस्थागत समीक्षा की नई पहल

-डॉ. सत्यवान सौरभ-

लोकतंत्र की सफलता केवल जनता की भागीदारी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इससे भी अधिक इस बात पर आधारित होती है कि शासन-तंत्र कितना जवाबदेह, पारदर्शी और परिणामोन्मुख है। भारत जैसे विशाल और बहुस्तरीय लोकतंत्र में यह प्रश्न कई गुना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या मंत्री-जो विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष प्रशासक हैं-अपने विभाग के कार्य, नीतियों और दैनिक प्रशासनिक निर्णयों के प्रति पर्याप्त रूप से उत्तरदायी हैं? समय-समय पर यह चिंता व्यक्त की जाती रही है कि शासन में पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का अभाव और नीतिगत अस्पष्टता जैसी समस्याएँ निर्णय-प्रक्रिया को कमजोर करती हैं।

इन्हीं परिस्थितियों में यह विचार उभरता है कि मंत्रियों के कार्य-काज की नियमित रिपोर्ट तैयार की जाए और उसकी समीक्षा सदन के अध्यक्ष द्वारा की जाए। यह प्रस्ताव मात्र प्रशासनिक सुधार नहीं है; यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति-संतुलन, नैतिक जिम्मेदारी और जन-विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

भारत की संवैधानिक संरचना में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका के रूप में मंत्री शासन-व्यवस्था की धुरी होते हैं, परंतु उनकी जवाबदेही अक्सर केवल चुनावी परिणामों या राजनीतिक आलोचनाओं तक सीमित रह जाती है। यदि इनके दायित्वों और निर्णयों का नियमित आकलन एक संस्थागत प्रक्रिया के अंतर्गत हो, तो शासन न केवल अधिक पारदर्शी होगा बल्कि जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी भी बन सकेगा।

मंत्रियों की कार्य-रिपोर्ट तैयार करने का विचार शासन के उस बुनियादी सिद्धांत को मजबूत करता है, जिसमें कार्यपालिका को अपनी प्रत्येक गतिविधि का तर्कसंगत विवरण देना होता है। एक व्यवस्थित रिपोर्ट मंत्री को बाध्य करती है कि वह अपने विभाग की वास्तविक स्थिति, योजनाओं की प्रगति, वित्तीय उपयोग, चुनौतियों और भविष्य के लक्ष्यों को सत्य और स्पष्ट रूप में वर्णित करे। यह दस्तावेज़ किसी राजनीतिक भाषण या प्रचार की तरह नहीं, बल्कि शासन का एक प्रामाणिक रिकॉर्ड बनता है।

यदि इस रिपोर्ट की समीक्षा सदन अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो इसकी विश्वसनीयता और गंभीरता दोनों ही बढ़ जाती हैं। सदन अध्यक्ष भारतीय लोकतंत्र में तटस्थता के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। उनकी भूमिका केवल सदन की कार्यवाही का संचालन करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे विधायी नैतिकता और संसदीय मर्यादाओं के संरक्षक भी होते हैं। उनकी समीक्षा एक निष्पक्ष, संतुलित और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

यह तर्क दिया जा सकता है कि ऐसी प्रणाली मंत्री की स्वतंत्रता को सीमित कर देगी। परंतु यह समझना आवश्यक है कि लोकतंत्र में किसी भी पद की स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ जुड़ी होती है, उससे अलग नहीं होती। जब एक मंत्री जानता है कि उसके प्रत्येक निर्णय का औपचारिक दस्तावेज़ बनकर समीक्षा के लिए जाएगा, तो वह नीतिगत गंभीरता और प्रशासनिक अनुशासन को और मजबूत रूप से अपनाता है।

इसके साथ ही, एक ऐसी रिपोर्टिंग व्यवस्था शासन में निरंतरता भी सुनिश्चित करती है। मंत्रालयों में मंत्रियों का परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया है, परंतु अक्सर नीतियाँ इसी संक्रमण में कमजोर पड़ जाती हैं क्योंकि नई नेतृत्व टीम को पिछली प्रगति की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। नियमित रिपोर्टें इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती हैं। इससे शासन में न केवल पारदर्शिता बढ़ती है बल्कि नीतिगत निरंतरता और प्रशासनिक स्थिरता भी सुनिश्चित होती है।

दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में ऐसी व्यवस्थाएँ पहले से मौजूद हैं। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में मंत्रियों की नियमित रिपोर्ट संसद या उसकी समितियों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यह प्रक्रिया दिखाती है कि जवाबदेही केवल राजनीतिक आलोचना का विषय नहीं है, बल्कि शासन का एक अनिवार्य अंग है। भारत में यदि यह प्रणाली लागू होती है, तो यह वैश्विक मानकों के अनुरूप एक आधुनिक और पारदर्शी प्रशासनिक ढाँचा स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम होगा।

ऐसी रिपोर्टिंग प्रणाली का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष जनता का अधिकार है। भारत में नागरिक बार-बार यह भावना व्यक्त करते हैं कि शासन-तंत्र उनके प्रति पर्याप्त रूप से पारदर्शी नहीं है। योजनाओं की प्रगति, बजट का वास्तविक उपयोग और समय-सीमाएँ अक्सर अस्पष्ट रहती हैं। इस प्रस्ताव के लागू होने से जनता को भी मंत्रालयों के कार्य-काज का प्रामाणिक सार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे एक स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद स्थापित होगा।

सदन अध्यक्ष द्वारा की गई समीक्षा आलोचना का रूप नहीं होगी; यह सुधारात्मक प्रक्रिया का एक हिस्सा बनेगी। समीक्षा से मिली टिप्पणियाँ मंत्री के लिए दिशानिर्देश बन सकती हैं, जो विभाग की कार्यक्षमता और नीतियों की गुणवत्ता को और ऊँचा उठाने में मदद करेंगी। जब तंत्र निष्पक्ष निगरानी के साथ चलता है, तो लापरवाही और विलंब जैसी समस्याएँ स्वतः ही कम हो जाती हैं।

यह प्रस्ताव शासन की उस बुनियादी धारणा को फिर से स्थापित करता है कि सत्ता का उद्देश्य केवल अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। मंत्री जब अपने दायित्वों का नियमित लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हैं, तो वे न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता में योगदान देते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता को भी मजबूत करते हैं।

निष्कर्षतः, मंत्रियों की कार्य-रिपोर्ट और सदन अध्यक्ष द्वारा उसकी समीक्षा एक ऐसी पहल है जो भारत के लोकतंत्र को अधिक जीवंत, अधिक पारदर्शी और अधिक विश्वसनीय बना सकती है। यह प्रस्ताव शासन के प्रत्येक स्तर को उत्तरदायित्व के नए मानदंडों के तहत लाने की क्षमता रखता है। यह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति के उन्नयन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

यदि भारत इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो यह लोकतंत्र की वास्तविक भावना-जन-उत्तरदायित्व, सच्ची सेवा और पारदर्शी शासन-को और मज़बूत करेगा। ऐसी प्रत्येक पहल लोकतंत्र को सिर्फ़ एक शासन-व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवंत और मूल्य-आधारित परंपरा बनाती है, जो समय के साथ और भी परिष्कृत होती जाती है।

नींद में कैसे करें ध्यान

धर्म कर्म

जिन्होंने जीवन की आंतरिक प्रक्रिया को देखा है वे गहराई के साथ कहते हैं कि प्रत्येक बार श्वास लेने के साथ तुम जन्मते हो और प्रत्येक श्वास छोड़ने के साथ तुम मरते हो। प्रत्येक क्षण जन्म लेते हो... कुछ मिनटों के लिए मौन, अंधेरा और विश्रांत शरीर-इनके संबंध में सजग रहो। जब तक पूरी तरह से नींद न आ जाए, तब तक ऊंघते समय सजग रहो और तुमको आश्र्चय होगा। जब तक पूरी तरह नींद आती है तब तक के अंतिम क्षण तक यदि तुम ऐसा अभ्यास जारी रखते हो तो फिर सुबह में भी पहला विचार सजगता के संबंध में ही होगा। सोते समय जो तुम्हारा अंतिम विचार होगा, वही सुबह में जागने पर पहला विचार होगा क्योंकि तुम्हारी नींद के दौरान यह अंतर-प्रवाह के रूप में जारी रहता है। ध्यान के लिए किसी के पास समय नहीं है-दिन में बहुत व्यस्तता रहती है। लेकिन रात के छह-आठ घंटों को ध्यान में बदला जा सकता है। तुम पानी से नहाते हो। ऐसा तुम सजगता के साथ क्यों नहीं करते हो? रोबोट की तरह यांत्रिक रूप से क्यों? तुम ऐसा हर रोज करते हो। इसलिए तुम करते जाते हो और यह यंत्रवत हो जाता है। हर काम जीवंत होकर करो। धीरे-धीरे तुम्हारा संपूर्ण दिन, चैबीसों घंटे ध्यान से भर जाएगा। तभी तुम सही मार्ग पर हो। तब तुम्हें सफलता मिलने की पूरी गारंटी है। रात को बत्ती बुझा दो, बिस्तर पर बैठ जाओ। और ओ ध्वनि करते हुए मुंह से गहरी श्वास छोड़ो। पूरी तरह से श्वास छोड़ने के बाद एक मिनट के लिए रुक जाओ। न तो श्वास लो और न ही छोड़ो-केवल रुक जाओ। इस ठहराव में तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। श्वास भी नहीं ले रहे हो। केवल एक क्षण के लिए उस ठहराव में रहो और साक्षी बनो। देखो कि क्या हो रहा है। सजग रहो कि तुम कहां हो। उस ठहराव के एक क्षण में संपूर्ण परिस्थिति के साक्षी बनो। वहां समय नहीं रहता क्योंकि समय श्वास के साथ चला जाता है। तुम श्वास ले ते हो इसलिए तुम महसूस करते हो कि समय बीत रहा है। समय रुक गया है तो सबकुछ रुक गया है उस ठहराव में तुम अपने अंतस और ऊर्जा के गहनतम स्त्रेत के प्रति सजग हो सकते हो। तब नाक से श्वास लो, श्वास लेने के लिए अतिरिक्त प्रयास मत करो। श्वास छोड़ने के लिए ही पूरा प्रयास करो। तुमने श्वास छोड़ दिया, फिर एक क्षण के लिए रुक जाओ, तब शरीर को श्वास लेने दो।

आज का इतिहास

1907 - भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित डकैती की पहली घटना चिंगरीपोटा रेलवे स्टेशन पर हुई।
1917 - फिनलैंड ने रुस से स्वतंत्रता की घोषणा की।
1921 - ब्रिटिश सरकार और आयरिश नेताओं के बीच हुई एक संधि के बाद आयरलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का स्वतंत्र सदस्य घोषित किया गया।
1926 - फिराक गोरखपुरी अपने साहित्यिक जीवन के आरंभिक समय में ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक बंदी बनाए गए थे।
1946 - होमगार्ड संगठन की स्थापना की गई।
1978 - यूरोपीय देश स्पेन में संविधान को अंगीकार किया गया।
1978 - स्पेन में 40 साल के तानाशाही शासन के बाद देश के नागरिकों ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतदान किया। यह जनमत संग्रह संविधान की स्वीकृति के लिए कराया गया।
1983 - यरुशलम में एक बस धमाके में छह नागरिकों की मौत।
1990 - युद्ध टालने के प्रयासों के तहत इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इराक और कुवैत में बंधक बनाये गये सभी विदेशी बंधकों की रिहाई का आदेश दिया।
1992 - अयोध्या का विवादित बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया। इसके फलस्वरूप हुई हिंसा में करीब 400 लोग मारे गये।
1997 - क्योटो (जापान) में अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन प्रारम्भ।
1998 - बैंकॉक में 13वें एशियाई खेलों की शुरुआत, इटली को हराकर स्वीडन लगातार दूसरी बार डेविस कप विजेता बना।
1998 - ह्यूगो शावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गये।
1999 - इंडोनेशियाई जेल से 283 क़ैदी फ़रार।
2001 - अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान हथियार डालने पर सहमत।
2002 - स्पेन के कार्लोस मोया को 'एटीपी यूरोपियन प्लेयर आफ़ द इयर' ख़िताब दिया गया।
2007 - आस्ट्रेलिया के स्कूलों में सिक्ख छात्रों को कृपण साथ ले जाने और मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं में हिजाब पहनकर जाने की इजाजत मिली।
2008 - केन्द्रीय बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेट में एक प्रतिशत की कटौती की।

पुतिन की भारत यात्रा 2025- वैश्विक शक्ति-समीकरण के केंद्र में भारत-रूस की नई साझेदारी

-किशन सनमुखदास भावनानी-

वैश्विक स्तरपर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है, 4-5 दिसंबर 2025 क़ी भारत यात्रा न केवल दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन के संदर्भ में भी अत्यंत निर्णायक मानी जा रही है। वर्ष 2022 में यूक्रेन संघर्ष आरंभ होने के बाद यह पुतिन की पहली भारत यात्रा है, इसलिए पूरी दुनियाँ की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हैं। भारत और रूस के ऐतिहासिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंध दशकों से अटूट रहे हैं, किंतु इस बार की यात्रा कई नए आयाम खोलने वाली मानी जा रही है जो 21वीं सदी के भू-राजनीतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि भारत और रूस के संबंध सदैव समानता, सम्मान और पारस्परिक विश्वास पर आधारित रहे हैं।

सामरिक हथियारों, ऊर्जा आपूर्ति, अंतरिक्ष तकनीक नागरिक परमाणु सहयोग तथा रक्षा उत्पादन में दोनों देशों की साझेदारी दुनिया के बड़े रणनीतिक गठबंधनों की तुलना में कहीं अधिक स्थिर और दीर्घकालिक साबित हुई है। पुतिन की इस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य इन साझेदारियों को आधुनिक वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप पुनर्गठित करना तथा आने वाले दशकों के लिएव्यापक सहयोग का नया मार्ग तैयार करना है। विशेषकर ऊर्जा सुरक्षा, आर्कटिक सहयोग, समुद्री संपर्क, डिजिटल मुद्रा-प्रणाली और रक्षा नवाचारों में दोनों देशों के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ताएँ होने की संभावना है। आज जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति बहुध्रुवीय संरचना की ओर तेजी से बढ़ रही है, भारत और रूस दोनों ही इस नए वैश्विक क्रम में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता को सर्वाधिक महत्व देते हैं। भारत एक ओर अमेरिका, यूरोपीय संघ और क़्वाड देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस उसके सबसे विश्वसनीय रणनीतिक साझेदारों में बना हुआ है। इसी कारण पुतिन की यह यात्रा भारत के मल्टी-अलाइनमेंट दृष्टिकोण को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह यात्रा यह भी दर्शाती है कि भारत वैश्विक कूटनीति के भीतर एक सेतु-राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, जो पूर्व और पश्चिम दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने में सक्षम है। यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए व्यापक आर्थिक प्रतिबंधों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार-व्यवस्था को बदल दिया है। ऐसे समय में भारत की भूमिका रूस के लिए अत्यधिक महत्व की हो गई है। ऊर्जा आपूर्ति, वैकल्पिक भुगतान-प्रणाली, समुद्री मार्गों के विकास और वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ संवाद में भारत रूस का प्रमुख सहयोगी बनकर उभरा है। पुतिन की यात्रा इस सहयोग को एक नई संस्थागत मजबूती देने का अवसर प्रदान करती है। विशेषकर रुपए-रूबल व्यापार, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे और सुदूर-पूर्व रूस में भारतीय निवेश जैसे मुद्दे इस यात्रा के केंद्र में रहने की संभावना रखते हैं।

साथियों बात अगर हम रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को समझने की करें तो, पुतिन की यह राजकीय यात्रा कई मायनों में खास होगी, यह भारत और रूस, दोनों के नेतृत्व को अपने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए दृष्टिकोण निर्धारित करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगीमॉस्को से मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रूस और भारत अपनी राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों (नेशनल पेमेंट सिस्टम) को जोड़ने के इच्छुक हैं और दिसंबर में जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली का दौरा करेंगे तो यह विषय एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। भारत और रूस के बीच पुराने और मजबूत संबंध दुनियाँ जानती है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। यूक्रेन युद्ध, बदलती वैश्विक राजनीति, डिफेंस डील्स और भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय भूमिका-इन सबके बीच रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण सटीक मायने रख़ता है।

साथियों बात अगर हम रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा की विशेषता का विश्लेषण करें तो, यह यात्रा कई दृष्टियों से ऐतिहासिक है। यह 23वाँ भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जो इस दीर्घकालिक साझेदारी की निरंतरता का प्रतीक है। यूक्रेन संघर्ष के बाद पुतिन का भारत आना यह भी दर्शाता है कि रूस भारत को एक विश्वसनीय, तटस्थ और प्रभावशाली साझेदार के रूप में देखता है। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को आधुनिक वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्जीवित करना है।

बदलते आर्थिक तंत्र, तकनीकी प्रगति, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा आधुनिकीकरण और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था कीवास्तविकताओं को देखते हुए दोनों देशों के लिए यह बैठक नई संभावनाओं और नए समझौतों का मार्ग खोल सकती है। (1) रक्षा सहयोग-रणनीतिक सुरक्षा की धुरीपुतिन-मोदी वार्ता में रक्षा सहयोग मुख्य केंद्र में रहने की संभावना है। भारत अपनी वायु रक्षा संरचना को सुदृढ़ करने के लिए रूस से अतिरिक्त एस-400 वायु-रक्षा रेजिमेंट प्राप्त करने पर विचार कर सकता है। साथ ही, लड़ाकू विमानों, मिसाइल प्रणालियों हेलीकॉप्टरों और उन्नत सैन्य तकनीकों के संयुक्त उत्पादन पर गंभीर विमर्श संभावित है। भारत लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय निर्माण क्षमता को बढ़ावा देना चाहता है, और रूस इस दिशा में एक प्रमुख साझेदार बना रह सकता है। पुराने रक्षा प्लेटफार्मों जैसे सु-30एम क़ेआई के उन्नयन, भविष्य की प्रणालियों जैसे एस-500 तथा अन्य उन्नत एंटी-मिसाइल प्रणालियों पर भी चर्चा संभव है। यह सहयोग भारत की सामरिक स्वायत्तता के लिए अनिवार्य है। (2)आर्थिक, ऊर्जा और औद्योगिक साझेदारी-इस यात्रा के आर्थिक आयाम अत्यंत व्यापक हैं। दोनों देश एक व्यापक 2030 रणनीतिक आर्थिक रोडमैप को अंतिम रूप दे सकते हैं, जिसमें ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष, कृषि, खनन और औद्योगिक सहयोग शामिल हो सकते हैं। रूस भारत को कच्चे तेल, एलएनजी, कोयला तथा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दीर्घकालीन प्रस्ताव दे सकता है। छोटे मॉड्यलूर रिएक्टरों में सहयोग भी भविष्य के ऊर्जा विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। दूसरी ओर, भारत अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए रूस को एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्त्रोत तथा निवेश साझेदार के रूप में देखता है।

औद्योगिक, वैज्ञानिक और तकनीकी साझेदारी से दोनों देशों के हितों को समान रूप से लाभ मिल सकता है। (3) भुगतान प्रणाली और वित्तीय स्वायत्तता-इस यात्रा का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहलू दोनों देशों की राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों-भारत की "रु-पे " और रूस की "एम आईआर को जोड़ने का प्रस्ताव है। यह कदम दोनों देशों को पश्चिमी वित्तीय तंत्र, विशेषकर स्विफ्ट, से आंशिक स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। इससे पर्यटकों व्यवसायियों और छात्रों को लेन-देन में सीधी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही रुपया-रूबल व्यापार को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जो वैश्विक व्यापार में डॉलर पर निर्भरता घटाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा। यद्यपि इस प्रक्रिया की तकनीकी और नियामकीय चुनौतियाँ कम नहीं, फिर भी यह पहल दोनों देशों के लिए वित्तीय आत्मनिर्भरता का मार्ग खोल सकती है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर-7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व बी-142/2, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 से प्रकाशित।
संपादकीय एवं संपर्क कार्यालय ए-152 सेक्टर-63, नोएडा-201301 **संपादक - आदित्य वशिष्ठ** कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा आर.एन.आई. DELHIN/2012/42452
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। e-mail: Jbttimes2021@ gmail. Com

एलसीए तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमान के लिए भारत को अमेरिका से मिला पांचवां जीई-404 इंजन

बुनियादी समस्याओं का समाधान होने के बाद विमान के उत्पादन में तेजी आने की उम्मीद बढ़ी

नई दिल्ली। अमेरिकी इंजन निर्माता कंपनी जीई एयरोस्पेस ने शुक्रवार को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) मार्क-1 ए के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को पांचवां जेट इंजन सौंप दिया।

इस वित्त वर्ष के अंत तक भारत को 12 जीई-404 इंजन मिलने की उम्मीद है। एचएएल को मार्च से नए विमान की आपूर्ति करनी थी, लेकिन इसमें लगने वाले इंजन की अमेरिका से आपूर्ति में देरी की वजह से इंतजार लंबा हो गया। अब इंजन को लेकर बुनियादी समस्याओं का समाधान होने के बाद विमान के उत्पादन में तेजी आने की उम्मीद बढ़ी है।

भारत ने फरवरी, 2021 में एचएएल के साथ 83 तेजस मार्क-1ए विमानों के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का एक समझौता किया था। इस अनुबंध में 73 लड़ाकू जेट और 10 प्रशिक्षक विमान शामिल थे। भारतीय वायु सेना को 2024 में पहली खेप मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इस बीच कंपनी जीई एयरोस्पेस (जीई) ने एफ-404 इंजन का उत्पादन बंद कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने इसी साल 25 सितंबर को एचएएल के साथ अतिरिक्त 97 एलसीए मार्क-1ए लड़ाकू विमानों के नए ऑर्डर का अनुबंध किया है, जिसमें 68 सिंगल-सीट लड़ाकू विमान और 29 ट्विन-सीट ट्रेनर विमान हैं, जिनकी डिलीवरी 2027-28 में शुरू होकर छह वर्षों में पूरी होगी। इस तरह एचएएल को भारतीय वायु सेना के लिए 180 विमानों का निर्माण करना है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कंपनी ने इसी साल 26 मार्च को पहला इंजन भारत को सौंपा। इसके बाद 13 जुलाई को जीई ने दूसरा इंजन भेजा। एचएएल को एलसीए मार्क-1ए के लिए तीसरा जीई-404 इंजन 11 सितंबर को मिला। कंपनी ने उसी समय एक और इंजन सितंबर के अंत तक देने का वादा किया था, जिसकी आपूर्ति 30 सितंबर को की गई। भारत को चार इंजन मिलने के बाद एलसीए मार्क-1ए विमानों के उत्पादन और आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद बढ़ी है। अमेरिकी इंजन निर्माता कंपनी जीई एयरोस्पेस ने पांचवां इंजन आज एचएएल को सौंप दिया। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत को 12 जीई-404 इंजन मिलने की उम्मीद है। ये इंजन भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान में लगाए जायेंगे, जिसे भारतीय वायु सेना में शामिल किया जा रहा है।

एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. डीके सुनील ने कहा कि एचएएल जीई के एफ-414 इंजनों के लिए 80 फीसदी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी बातचीत कर रहा है, जो उन्नत एलसीए मार्क-2 और स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) को शक्ति प्रदान करेगा। डॉ. सुनील ने कहा कि जीई ने हमें एक साल में 12 इंजन देने का वादा किया था, लेकिन अब शायद हमें वित्तीय वर्ष के अंत तक 12 इंजन मिल जाएंगे। इस साल हमें 10 इंजन मिल सकते हैं। बाकी इंजन हमें अगले साल मार्च तक मिल जाएंगे। हम 10वें विमान का ढांचा बना चुके हैं और 11वां विमान तैयार है। इंजन को लेकर बुनियादी समस्याओं का समाधान हो गया है, इसलिए अब उत्पादन में तेजी आएगी। जीई ने अगले साल 20 इंजन देने का वादा किया है, जिसके लिए शीर्ष प्रबंधन के साथ एक बैठक की है।

स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 लोकसभा से पारित

नई दिल्ली। लोकसभा ने शुक्रवार को स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। यह विधेयक पान मसाला और गुटखा जैसी वस्तुओं के उत्पादन पर एक नया उत्पादन-आधारित उपकर लगाने का प्रावधान करता है। सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फंड जुटाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में विधेयक के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस लगाने का प्रस्ताव है, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा- दोनों महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए लक्षित उपयोग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि यह उपकर उन वस्तुओं पर लगाया जाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और जिनकी खपत को हतोत्साहित करना आवश्यक है। विधेयक के अनुसार उपकर उन व्यक्तियों या इकाइयों पर लगेगा जो पान मसाला, गुटखा और अन्य निर्दिष्ट उत्पादों के उत्पादन में मशीनें या मैनुअल यूनिट्स संचालित करते हैं। करदाताओं को अपने उत्पादन क्षमता के आधार पर मासिक रूप से उपकर की स्वतः गणना करनी होगी और मासिक रिटर्न दाखिल करना होगा। मशीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर उपकर दरें तय होंगी। उदाहरण के लिए एक मशीन जो प्रति मिनट 500 तक पाउच (प्रति पाउच 2.5 ग्राम तक) बनाती है, उसे 1.01 करोड़ रुपये प्रति माह उपकर देना होगा। 1,001–1,500 पाउच प्रति मिनट उत्पादन क्षमता वाली मशीनें (पाउच वजन 10 ग्राम से अधिक) 25.47 करोड़ रुपये प्रति माह उपकर भरेंगी। मैनुअल उत्पादन इकाइयों के लिए 11 लाख रुपये प्रति माह की निश्चित उपकर दर होगी। सरकार को सार्वजनिक हित में इन दरों को दोगुना तक बढ़ाने का अधिकार होगा। विधेयक में प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर के निरीक्षण प्रावधान किए गए हैं। आयुक्त स्तर के अधिकारी उत्पादन इकाइयों का ऑडिट और अवैतनिक या कम भुगतान किए गए उपकर की वसूली करेंगे। संयुक्त आयुक्त या उससे ऊपर के अधिकारी निरीक्षण, तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर सकेंगे। उपकर चोरी में सहायता करने वालों पर 10 हजार रुपये अथवा बचाए गए उपकर की राशि (जो भी अधिक हो) तक का दंड लगेगा। एक करोड़ रुपये से अधिक की चोरी के मामलों में एक से पांच वर्ष तक की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा, आदेशों के खिलाफ तीन-स्तरीय अपील प्रणाली—अपील प्राधिकरण, कस्टम्स-एक्साइज-सेवा कर अपीलीय अधिकरण और महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर उच्च न्यायालय—का प्रावधान किया गया है। सीतारमण ने स्पष्ट किया कि सेस लगाने की संवैधानिक शक्ति अनुच्छेद 270 में निहित है, जो विशेष उद्देश्य के लिए संसद को उपकर लगाने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि यह धारणा गलत है कि केंद्र सरकार 2014 के बाद सेस लगाने लगी। वर्ष 1974 में कच्चे तेल पर सेस लगाया गया था। 2000 में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस शुरू हुआ।

अरुणाचल प्रदेश के तीन युवकों ने सेना की अग्निवीर परीक्षा पास की

इटानगर। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले के सुदूर आलो क्षेत्र के तीन युवाओं ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। रक्षा प्रवक्ता के अनुसार चयनित उम्मीदवार-जारी बगरा, टोनी दोजी और यम्पर नाडा-अब औपचारिक भर्ती के लिए जोरहाट स्थित असम रेजिमेंट भर्ती कार्यालय जाएंगे। रक्षा जनसम्पर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि अलोंग और बसार क्षेत्रों के रहने वाले इन तीनों युवाओं ने भौगोलिक चुनौतियों, सीमित प्रशिक्षण सुविधाओं और संसाधनों की कमी के बावजूद कठोर तैयारी और दृढ़ संकल्प के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है। यह सफलता सीमा क्षेत्रों में भारतीय सेना के निरंतर मार्गदर्शन और पहुंच कार्यक्रमों का प्रमाण है।

वक्फ पंजीकरण की समयसीमा नहीं बढ़ेगी, पंजीकरण का प्रयास करने वाले मुत्तवलियों को राहत देंगे: रिजिजू

नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 'उम्मीद' पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने की संभावना से शुक्रवार को इनकार किया और कहा कि उन 'मुत्तवलियों' (वक्फ का देखभाल करने वाले) को तीन महीने तक जुर्माने और किसी कठोर सजा से राहत दी जाएगी, जो पंजीकरण करने का प्रयास करते हुए किसी वजह से सफल नहीं हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि शुक्रवार सुबह तक 1.51 लाख संपत्तियों का पंजीकरण हो चुका था। मंत्री का यह भी

कहना था कि जो लोग पंजीकरण नहीं कर पाए हैं वो वक्फ न्यायाधिकरण का रुख कर सकते हैं। केंद्र ने सभी वक्फ संपत्तियों की 'जियो-टैगिंग' के बाद एक डिजिटल सूची बनाने के लिए बीते छह जून को एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (उम्मीद) अधिनियम केंद्रीय पोर्टल शुरू किया था। 'उम्मीद' पोर्टल के प्रावधान के अनुसार, देश भर में सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से छह महीने के भीतर अपलोड किया जाना है। पंजीकरण के लिए छह महीने की मियाद शुक्रवार को खत्म हो रही है। रिजिजू ने संवाददाताओं से कहा, "वक्फ कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल शुरू किया था और सभी वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए संबंधित पक्षों को छह महीने की अवधि दी गई थी। आज आखिरी दिन है और अब भी लाखों संपत्तियों का पंजीकरण नहीं हो सका है। कई सांसदों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने पोर्टल की मियाद बढ़ाने का आग्रह किया।" उन्होंने बताया कि अब तक उम्मीद पोर्टल पर 1.51 लाख वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण हुआ है। मंत्री ने कहा, "मैं उन भी मुतवल्लियों को आश्वस्त करता हूं कि अगले तीन महीनों तक कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे या कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे जिन्होंने पंजीकरण की कोशिश की।

कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से स्थिति गंभीर

कोलकाता। कोलकाता हवाई अड्डे पर इंडिगो विमानसेवा का परिचालन पिछले तीन दिनों से बुरी तरह प्रभावित रहा। पहले से जारी रद्दीकरण और विलम्ब के अलावा इंडिगो की 47 अतिरिक्त उड़ानों के रद्द होने से स्थिति और गंभीर हो गई है। नई जानकारी के अनुसार, 4 दिसम्बर को कोलकाता से देश के विभिन्न शहरों जैसे- मुम्बई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, इंदौर, गुवाहाटी, कोयंबटूर आदि मार्गों पर इंडिगो की 47 उड़ाने रद्द की गईं। इन रद्द उड़ानों में सुबह 03:15 बजे से लेकर रात 19:30 बजे तक का समय प्रभावित रहा। कोलकाता आने वाली फ्लाइटों में चार दिसम्बर को 22 रद्द हुईं और 81 देर से पहुंची। वहीं यहां से जाने वालीं फ्लाइटों में 17 रद्द की गईं और 78 देर से रवाना हुईं। यानी कि एक ही दिन में कुल 39 उड़ाने रद्द हुईं और 159 उड़ानो में विलम्ब हुआ। वहीं, 5 दिसम्बर को सुबह 9 बजे तक भी स्थिति सामान्य नहीं रहीं। यहां से जाने वाली 8 उड़ाने रद्द की गईं और 13 देर से रवाना हुईं। जबकि जाने वाली वाली में 18 रद्द हुईं और 13 ने देर उड़ान भरी।

मुख्यमंत्री ने की इन्वेस्ट यूपी के सभी कंट्री डेस्क की समीक्षा

'स्पीड, स्टेबिलिटी और सपोर्ट' से और तेज होगा यूपी का औद्योगिक विकास: मुख्यमंत्री

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, एफडीआई बढ़ाने को बढ़ाएं संवाद, तेज करें प्रयास
- फॉर्च्यून 500 नीति के तहत 11 कंपनियों ने 13,610 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए
- विदेशी कंपनियों का यूपी की ओर बढ़ता भरोसा, निवेश प्रस्तावों में निरंतर बढ़ोतरी
- एफडीआई नीति 2023 के तहत 56 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्रक्रियाधीन
- चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में आया 683 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश में विदेशी निवेश को नई रफ्तार देने के लिए चल रहे प्रयासों की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए साफ कहा कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ निवेश की संभावना नहीं, बल्कि निवेश के भरोसे का राज्य बन गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर निवेशक के साथ संवाद लगातार बना रहना चाहिए और किसी भी स्तर पर देरी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि 'स्पीड, स्टेबिलिटी और सपोर्ट' यही नए उत्तर प्रदेश की पहचान होनी चाहिए। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के सितंबर 2025 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश को 683 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है और राज्य का कुल संचयी विदेशी निवेश अक्टूबर 2019 से अब 2,754 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि चालू अवधि में प्रदेश को 5,963 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश प्रवाह मिला है, जो पिछले वर्षों की तुलना में तेज वृद्धि को दर्शाता है। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि एफडीआई-एफसीआई-फॉर्च्यून 500 नीति-2023 के तहत अब तक 11 निवेश आवेदकों ने 13,610 करोड़ रुपये के प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा 22 आवेदनों के माध्यम से 17,810 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 56 हजार करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े 29 आवेदन पाइपलाइन में हैं।

यह भी बताया गया कि जापान, अमेरिका, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड और सिंगापुर उत्तर प्रदेश के प्रमुख निवेश साझेदार बने हुए हैं। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर और खाड़ी देशों के लिए बनाए गए विदेशी देश डेस्क लगातार सक्रिय हैं। दूतावासों, उच्चायोगों और व्यापार संघों से निरंतर संवाद चल रहा है। निवेशकों के साथ 100 से अधिक वन-टू-वन बैठकें हो चुकी हैं। जापान व्यापार संगठन और सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के साथ होने वाले समझौते भी निवेश के ठोस अवसरों में बदले जा रहे हैं। खाड़ी सहयोग परिषद सेक्टर डेस्क की समीक्षा में बताया गया कि दिल्ली, नोएडा, मुंबई, लखनऊ और कानपुर में अब तक 6 गोलमेज बैठकें हो चुकी हैं, जिनसे 83 कंपनियों के साथ सीधा संवाद बना और करीब 5,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए। सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक रुचि दिखी, जबकि बैंकिंग, वित्त, बीमा, फार्मा, लाइफ साइंस, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्रों को उच्च संभावनायुक्त बताया गया।

मुख्यमंत्री ने ललितपुर फार्मा पार्क को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए कि इससे जुड़े अवसंरचना कार्यों में और तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि कई बड़ी दवा कंपनियों ने यहां निवेश में रुचि दिखाई है, ऐसे में उनसे लगातार संवाद बनाए रखा जाए और भूमि, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं समय पर सुनिश्चित हों। जापान डेस्क की समीक्षा में बताया गया कि डेंसो के ब्राउनफील्ड विस्तार परियोजना पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और दस्तावेजी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कांसाई फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन की 125 जापानी कंपनियों के साथ फॉलोअप चल रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। टोयोटा समूह, सुमितोमो और मारुबेनी से निवेश को लेकर लगातार बातचीत जारी है। जापान डेस्क के अंतर्गत कुल 20,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

ताइवान डेस्क को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यहां प्रयास और तेज किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि ताइवान के निवेशकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा जाए, केवल रोड शो तक सीमित न रहा जाए। बैठक में बताया गया कि 40 से अधिक कंपनियां चिन्हित की गई हैं और लगभग 100 करोड़ रुपये के निवेश की पाइपलाइन तैयार है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां एचसीएल-फॉक्सकॉन का 3,700 करोड़ रुपये का निवेश मजबूत आधार बनेगा।

कानपुर को तकनीकी वस्त्र और स्पोर्ट्सवेयर केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना भी सामने रखी गई। दक्षिण कोरिया डेस्क की समीक्षा में बताया गया कि सैमसंग, एलजी, केएच वेटेक और ड्रीमटेक जैसी कंपनियों के साथ निवेश को लेकर बातचीत आगे बढ़ चुकी है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का गौतमबुद्ध नगर में करीब 850 करोड़ रुपये का विस्तार प्रस्तावित है, जबकि लोट्टे समूह का लगभग 400 करोड़ रुपये का निवेश प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री ने कोरियाई कंपनियों के लिए भी संवाद और सुविधाकरण को और मजबूत करने के निर्देश दिए। सिंगापुर डेस्क के अंतर्गत टेमासेक, सरकारी निवेश कोष, पीएसए, डीबीएस, कैपिटललैंड-असेंडास, केपेल और सेम्बकॉर्प जैसे निवेशक यूपी में लगातार रुचि दिखा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी विदेशी डेस्क द्वारा नियमित अंतराल पर राउंड टेबल बैठकें होती रहनी चाहिए। उन्होंने इन्वेस्ट यूपी की टीम से कहा कि हर निवेशक के साथ एकल संपर्क बिंदु तय हो, ताकि उसे प्रणाली में भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री ने उद्योगों को गति देने के लिए 'प्लग एंड प्ले' मॉडल पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि निवेशक को पहले दिन से तैयार अवसंरचना मिलेगी, तो वह तेजी से काम शुरू कर सकेगा और यही मॉडल उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों से आगे ले जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां कंपनियों के कॉरपोरेट और मुख्यालय खोलने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को लेकर यह भी निर्देश दिए कि वहां आवश्यक मानव संसाधन की कमी न रहे।

स्थानीय उद्योग, निर्यात और रोज़गार को नई ऊंचाई देगा ओडीओपी 2.0: मुख्यमंत्री

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ब्रांड उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी 'एक जनपद- एक उत्पाद योजना' अब अपने अगले चरण ओडीओपी 2.0 टू के माध्यम से स्थानीय उद्योग, स्वरोज़गार और निर्यात को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक बाजार, आधुनिक मांग, तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता और पैकेजिंग की नई आवश्यकताओं को देखते हुए ओडीओपी को अब और अधिक व्यापक, व्यावसायिक और परिणामोन्मुखी स्वरूप में आगे बढ़ाने की जरूरत है। ओडीओपी 2.0 के माध्यम से सरकार का लक्ष्य होगा कि प्रदेश के पारंपरिक उत्पाद बड़े बाज़ार, निर्यात और स्थायी रोजगार का मजबूत आधार बनें।

शुक्रवार को इस संबंध में हुई महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद की विशिष्ट खाद्य परंपरा को भी एक संगठित पहचान देने की दिशा में 'एक जनपद-एक व्यंजन' (ओडीओसी) की अवधारणा को साकार करने की भी जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि 'एक जनपद-एक व्यंजन' योजना उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा से जुड़ी हुई है। प्रदेश के हर क्षेत्र में खान-पान की कुछ न कुछ विशिष्ट परंपरा है। कहीं हलवा अच्छा है तो कहीं दालमोठ। उन्होंने कहा कि हर जिले के विशेष व्यंजनों की मैपिंग कर उनकी गुणवत्ता, स्वच्छता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन को सुदृढ़ किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'ओडीओपी' और 'ओडीओसी' मिलकर उत्तर प्रदेश को 'लोकल से ग्लोबल' की दिशा में नई गति देंगे। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2018 में प्रारंभ ओडीओपी योजना आज उत्तर प्रदेश के निर्यात और स्थानीय उद्योगों की रीढ़ बन चुकी है।

अब तक 1.25 लाख से अधिक टूलकिट वितरित किए जा चुके हैं, 06 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरण हो चुका है और 08 हजार से अधिक उद्यमियों को प्रत्यक्ष विपणन सहायता दी गई है। प्रदेश में तीस साझा सुविधा केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और 44 ओडीओपी उत्पादों को अब तक जियो टैग प्राप्त हो चुके हैं। ओडीओपी उत्पाद आज प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं और राज्य के कुल निर्यात में इनका योगदान पचास प्रतिशत से अधिक है। ओडीओपी को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने ओडीओपी 2.0 को लेकर कहा कि यह अब केवल एक योजना नहीं, बल्कि स्थायी रोजगार, स्थानीय उद्यम और निर्यात को नई ऊँचाई देने का सशक्त माध्यम बने। उन्होंने कहा कि अब उन इकाइयों और उद्यमियों को आगे बढ़ाने पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जिन्होंने पहले चरण में उत्कृष्ट कार्य किया है, ताकि वे अपने व्यवसाय का और विस्तार कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं को इस तरह आगे बढ़ाया जाए कि तकनीक, पैकेजिंग, गुणवत्ता और बाजार सहित चारों मोर्चों पर उत्तर प्रदेश के उत्पाद सशक्त रूप में स्थापित हों। बैठक में यह भी बताया गया कि ओडीओपी से जुड़े कॉमन फैसिलिटी सेंटरों को अब और अधिक उपयोगी बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कॉमन फैसिलिटी सेंटरों के साथ विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि छोटे उद्यमियों को तकनीकी परामर्श, डिज़ाइन, पैकेजिंग और उत्पादन से जुड़ा पूरा सहयोग एक ही स्थान पर सुलभ हो सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ओडीओपी उत्पादों को केवल पारंपरिक बाजारों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें बड़े रीटेल नेटवर्क और आधुनिक बाजारों से जोड़ा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित हो रहे यूनिटी मॉल में ओडीओपी के समर्पित केंद्र बनाए जाएं। साथ ही सभी प्रतिष्ठित रीटेल नेटवर्क के साथ संवाद कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां उत्तर प्रदेश के उत्पाद प्रमुख रूप से प्रदर्शित हों। बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि ओडीओपी उत्पादों की गुणवत्ता और पहचान को और सुदृढ़ करने के लिए उन्हें प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से प्रमाणन और ब्रांड मूल्य प्रदान किया जाएगा, जिससे वैश्विक बाजार में उत्तर प्रदेश के उत्पाद विशिष्ट पहचान बना सकें।

उत्तर प्रदेश से 2027 से समाजवादी पार्टी होगी साफ : ब्रजेश पाठक

सीतापुर। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीतापुर पहुंचे। उनके आगमन को लेकर भाजपा संगठन और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सक्रिय दिखाई दिया। खैराबाद टोल प्लाजा पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता, एमएलसी पवन सिंह सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीतापुर में उन्होंने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी पूरी तरह साफ हो जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ब्रजेश पाठक ने अभियान की प्रगति रिपोर्ट का विस्तार से अवलोकन किया। इसे और अधिक प्रभावी एवं तेज गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है और अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस काम को बड़ी गंभीरता पूर्वक करना है। एसआईआर देश हित में है। इसलिए पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता इसका महत्व समझे। पत्रकारों के प्रश्नों पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी व उसके मुखिया 2027 को लेकर अभी से हताश व निराश हैं। उन्हें संभावित हार दिख रही है। इसलिए एसआईआर को लेकर के उनके द्वारा गलत बयानबाजी की जा रही है। पाठक ने कहा कि आने वाले प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी साफ होने वाली है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव आयोग के निर्देशों को मानने वाली पार्टी है। इसलिए उसका एक-एक कार्यकर्ता इस अभियान में लगा हुआ है। समीक्षा बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री पाठक लोहरबाग वार्ड के बूथ नम्बर 216 पर पहुंचे। उन्होंने 'कुंडी खटकाओ' अभियान के तहत डोर-टू-डोर जनसंपर्क किया।

इस दौरान उन्होंने लोगों के घर जाकर उनसे सीधा संवाद किया। सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार आम नागरिक इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक रहने और लोकतांत्रिक अधिकारों का सही उपयोग करने की भी अपील की।

भारत नेपाल सीमा पर कनाडाई नागरिक गिरफ्तार

महाराजगंज। एक कनाडाई नागरिक को फर्जी वीजा का उपयोग करने के कारण भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली आव्रजन जाँच चौकी पर गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति को उसके पासपोर्ट से विमल डांस के रूप में पहचाना गया।

अधिकारियों ने बताया कि वह एक टैक्सी में नेपाल से भारत की यात्रा कर रहा था, तभी उसे सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के कर्मियों ने सीमा द्वार पर रोका और सत्यापन के लिए आव्रजन अधिकारियों को सौंप दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह असल में पंजाब के मोहाली का रहने वाला है। आव्रजन और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसके पासपोर्ट पर दिल्ली हवाई अड्डा आव्रजन कार्यालय का एक फर्जी स्टैंप मिला है। सोनौली थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह ने कहा कि वह जाली आव्रजन मुहर का इस्तेमाल करके नेपाल के रास्ते कनाडा जाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि, उसके पास कनाडा का पासपोर्ट है, लेकिन उसके पास भारत का वैध वीजा नहीं है। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसे जेल भेज दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए 1,751 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

एसआईआर में शत-प्रतिशत शुद्धिकरण से खिलेगा कमल : केशव प्रसाद मौर्य

प्रयागराज। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय, सिविल लाइंस में शुक्रवार को यमुनापार एवं गंगापार के मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य अतिथि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में भाजपा के समर्पित और राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं जैसा संगठन किसी के पास नहीं है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि बूथों पर बैठकर शत-प्रतिशत मतदाता गहन पुनरीक्षण कराएं तथा फर्जी, कम उम्र और घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर कराने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि, पहले घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर करें, फिर उन्हें देश से बाहर करने का कार्य शासन-प्रशासन करेगा। यदि एसआईआर में शत-प्रतिशत शुद्धिकरण हुआ तो प्रयागराज की बारहों सीटों में कमल ही कमल

खिलेगा और भाजपा 325 से अधिक सीटों के लक्ष्य को प्राप्त कर इतिहास रचेगी। उपमुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष बेवजह हो-हल्ला कर रहा है और फर्जी वोट जोड़ने का कुचक्र रच रहा है। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें अधिक क्या जीत लीं, विपक्ष अहंकार में चूर हो गया। अब फर्जी वोटरों की जमानत जब्त होगी और वे सैफई में नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों में खलबली मची है, सफाईकर्मियों सहित कई घुसपैठिए जांच में सामने आ रहे हैं। अब उन्हें दादा-दादी, नाना-नानी के प्रमाण देने होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का भविष्य उज्ज्वल है और समर्पित कार्यकर्ताओं को किसी पैरवी की आवश्यकता नहीं है। यमुनापार जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा आभार गंगापार जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने व्यक्त किया।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि बैठक का शुभारम्भ उपमुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर वंदे मातरम् के साथ किया। बैठक में विधानसभावार प्रगति की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में नीरज त्रिपाठी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, उत्तर मौर्य प्रभारी गंगापार, अमरनाथ यादव प्रवासी यमुनापार, सुरेन्द्र चौधरी विधान परिषद सदस्य,विधायक राजमणि कोल,गुरू प्रसाद मौर्य और सभी जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, अभियान के संयोजक एवं सह-संयोजक उपस्थित रहे।

रोहिंग्या, बांग्लादेशी समेत सभी घुसपैठिए होंगे देश से बाहर: मंत्री असीम अरुण

कन्नौज। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने शुक्रवार को कन्नौज में अवैध घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी सहित सभी विदेशी नागरिकों को चिन्हित कर उन पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री असीम अरुण ने बताया कि प्रदेश सरकार इस समय विशेष अभियान चलाकर ऐसे अवैध निवासियों की पहचान करा रही है। जो व्यक्ति बिना दस्तावेजों के अवैध तरीके से रह रहा है, उसे गिरफ्तार कर डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और बाद में उसे उसके मूल देश लौटाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। कार्यक्रम में अभ्युदय योजना पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना गरीब और वंचित वर्ग के युवाओं के लिए बड़ी उम्मीद बनी है। इस योजना के तहत कई छात्र-छात्राओं ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की प्री और मेन्स परीक्षा पास की है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग से पिछले साल यूपीपीसीएस में 250 बच्चे क्वालीफाई हुए थे । इस वर्ष ग्राफ बढ़कर 277 हो गया है। इस बार से कोचिंग में एनआईटी, जेई, क्लेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई को भी सम्मिलित किया जाएगा।

कार्यक्रम में मंत्री असीम अरुण ने समाजसेवी बिपिन दीक्षित और कन्हैया दीक्षित के साथ मिलकर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड में कोई भी गरीब असहाय व्यक्ति बीमार न पड़े, इसी संकल्प के साथ समाजसेवियों ने यह पहल की है। मंत्री ने लोगों से वृद्धाश्रमों और सड़क किनारे रहने वाले जरूरतमंदों की देखभाल करने, अलाव जलवाने और गर्म कपड़ों के वितरण जैसी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने की अपील भी की।

बीएलओ के रूप में तैनात प्रधानाध्यापिका की दिल का दौरा पड़ने से मौत, जांच के आदेश

अलीगढ़। अलीगढ़ जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के लिए बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के रूप में तैनात प्राथमिक विद्यालय की 59 वर्षीय प्रधानाध्यापिका की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उनके परिवार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

प्रधानाध्यापिका साधना वर्मा का बृहस्पतिवार को उनके घर में निधन हो गया। उन्हें चार नवंबर को शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के लिए तैनात किया गया था। उनके परिवार ने बताया कि उन्होंने हेवतपुर फगोई गांव में बीएलओ संबंधी अपने सभी कर्तव्यों को ''बिना किसी समस्या के'' निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया था। उनके बेटे चेतन ने आरोप लगाया कि वर्मा ''लंबे समय से भारी दबाव'' में थीं। वह अपनी बीएलओ संबंधी जिम्मेदारियों के कारण नहीं बल्कि अन्य समस्याओं के कारण परेशान थी। वह सेवानिवृत्ति के करीब थी इसलिये उन्हें परेशान किया जा रहा था। उन्होंने दावा किया, ''उनकी समस्याएं बीएलओ के रूप में उनके काम से संबंधित नहीं थीं बल्कि मुख्य रूप से उनके उप-प्राचार्य और राज्य शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के कारण थीं, जिन्होंने उन्हें बार-बार किसी न किसी बहाने से परेशान किया।'' चेतन ने दावा किया कि अधिकारियों के समक्ष बार-बार मामला उठाने के बावजूद उनकी मां को पांच महीने से वेतन नहीं मिला था, जिससे वह गंभीर तनाव में थीं।

बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राकेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उप-प्राचार्य पूजा चौधरी को जांच जारी रहने तक निलंबित कर दिया गया है। चौधरी के खिलाफ अनुशासनहीनता और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं।

बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी से पूर्व प्रदेश में सतर्कता और सुरक्षा बढ़ी

लखनऊ/अयोध्या/मथुरा। बाबरी मस्जिद विध्वंस (छह दिसंबर, 1992) की बरसी से पहले भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, श्री कृष्ण जन्म भूमि मथुरा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अयोध्या और मथुरा के साथ वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर और प्रयागराज जैसे प्रमुख जिलों में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

पुलिस के अनुसार, अयोध्या में चार दिसंबर से ही सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। राम मंदिर के पक्ष में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। हाल में धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है, ऐसे में छह दिसंबर को सुरक्षा एजेंसियां अत्यंत सतर्क हैं। अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गौरव ग्रोवर ने बताया कि जिले के सभी थानों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चार दिसंबर से अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है और छह दिसंबर तक सुरक्षा घेरा और कड़ा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस दौरान आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। एसएसपी ने कहा कि होटल, ढाबे, अतिथि गृह और धर्मशालाओं की लगातार जांच की जा रही है, और शहर के प्रवेश द्वारों पर वाहनों की भी निगरानी की जा रही है। अयोध्या के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आशुतोष तिवारी ने बताया कि छह दिसंबर को लेकर अयोध्या क्षेत्र में पैदल गश्त की जा रही है। पुलिसकर्मियों को राम मंदिर मार्ग और संवेदनशील स्थानों पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर एक संवेदनशील स्थल है। आगरा रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) शैलेश कुमार पांडेय ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और पूरे जिले में सतर्कता बढ़ा दी।

अधिकारियों ने बताया कि मंदिर परिसर और अन्य संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद, पांडेय ने निवासियों को आश्वस्त करने के लिए गोविंद नगर और कोतवाली के प्रमुख बाजार क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि शहर को जोन और सेक्टर में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जोन की निगरानी वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी करेंगे। बाहरी जिलों से अतिरिक्त बल, पीएसी, आरएएफ और अन्य विशेष इकाइयां तैनात की गई हैं। एसएसपी ने कहा, ''पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। किसी भी व्यक्ति या संगठन को ऐसी कोई भी नयी गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे शांति भंग होने का खतरा हो। धार्मिक स्थलों और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।'' उन्होंने बताया कि संवेदनशील इलाकों में खुफिया इकाइयां सक्रिय हैं और आयोजनों की आड़ में शांति भंग करने वाले संदिग्धों को हिरासत में लिया जा रहा है। राज्य भर में रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, जिला सीमाओं, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि हाल में दिल्ली में कार विस्फोट के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी गई है। कुछ हिंदू संगठन छह दिसंबर को ''शौर्य दिवस'' और कई मुस्लिम समूह इसे ''काला दिवस'' के रूप में मनाते हैं, जिससे यह दिन कानून व्यवस्था के लिए संवेदनशील बन जाता है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने घुड़सवार पदक विजेताओं को किया सम्मानित

नई दिल्ली। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को एफईआई एशियन इक्वेस्ट्रियन (घुड़सवारी) चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम को सम्मानित किया। पटाया में हुए इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट से छह सदस्यीय भारतीय दल ने टीम और व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में कुल 5 पदक जीतकर देश के लिए इतिहास रच दिया।

इवेंटिंग में आशीष लिमये ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक और टीम इवेंट में रजत पदक अपने नाम किया। ड्रेसाज में श्रुति बोरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन रजत पदक हासिल किए—दो व्यक्तिगत और एक टीम इवेंट में। टीम के अन्य सदस्य शशांक सिंह कटारिया व शशांक कनमुड़ी (इवेंटिंग) और दिव्याकृति सिंह व गौरव पुंडीर (ड्रेसाज) थे।

एथलीटों को सम्मानित करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि भारत अब उन खेलों में भी सफलता हासिल कर रहा है, जिनमें पहले वैश्विक स्तर पर हमारी उपस्थिति बेहद सीमित थी। उन्होंने कहा, "यह 10 साल पहले वाला भारत नहीं है। पिछले दशक में हमारे खेल इकोसिस्टम में जबरदस्त बदलाव आया है। सरकार खिलाड़ी और उसके पदक के बीच आने वाली हर बाधा को दूर करेगी। हम भारत में इक्वेस्ट्रियन के लिए अनुकूल स्पोर्ट्स व्यवस्था तैयार करेंगे ताकि खिलाड़ियों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए न जाना पड़े।" मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार एक साल के भीतर देश में एक क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करेगी, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए घोड़ों की आवाजाही में लंबे समय से आ रही समस्या का समाधान करेगा।

तीन रजत पदक विजेता श्रुति बोरा ने मंत्री के त्वरित कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा, "जैसे ही हमने अपनी चिंताएं साझा कीं, उन्होंने तुरंत इक्वाइन डिज़ीज़-फ्री ज़ोन पर काम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमें केवल कुछ खिलाड़ियों को बाहर भेजने के बजाय पूरा इकोसिस्टम तैयार करना होगा। जब यह व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, तो भारत में ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी—सब कुछ बेहद सुगम हो जाएगा।"

शेफाली आईसीसी की महीने की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार की दौड़ में

दुबई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में 87 रन की तेजतर्रार पारी खेलने और दो महत्वपूर्ण विकेट लेने वाली भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा को नवंबर महीने के लिए आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल के चोटिल हो जाने के कारण शेफाली को भारतीय टीम में जगह मिली थी। उन्हें फाइनल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था और अब वह महिलाओं के पुरस्कार के लिए नामांकित की गई तीन खिलाड़ियों में शामिल हैं। महिला वर्ग का पुरस्कार हासिल करने के लिए उन्हें संयुक्त अरब अमीरात की ईशा ओझा और थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इन दोनों ने बैंकॉक में पहली आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। यूएई की कप्तान ओझा ने सात टी-20 मैचों में 137.50 की स्ट्राइक रेट से 187 रन बनाए और सात विकेट लिए। उन्हें टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया था। प

खेल मंत्रालय ने 64 दिवसीय फिट इंडिया दौड़ के लिए पुणे के 'इन्फ्लूएंसर' के साथ गठजोड़ किया

नई दिल्ली। खेल मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम फिट इंडिया ने अपनी 64 दिवसीय दौड़ के लिए अल्ट्रा-धावक और 'इन्फ्लूएंसर' आशीष कासोदकर की अगुवाई वाले पुणे स्थित सिंपल स्टेप्स फिटनेस के साथ गठजोड़ किया है। यह दौड़ 24 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश की डोंग घाटी से शुरू हुई, जहां भारत अपना पहला सूर्योदय देखता है। इसका समापन अगले साल गणतंत्र दिवस पर गुजरात के गुहार मोती में होगा, जो देश का आखिरी सूर्यास्त स्थल है।

मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, "इस साझेदारी से फिटनेस को जीवनशैली बनाकर फिट इंडिया मिशन को मजबूत करने, देश भर में वृक्षारोपण और पर्यावरण जागरूकता को प्रोत्साहित करने, समावेशी भागीदारी से मजबूत सामुदायिक संबंध बनाने तथा स्वास्थ्य, आंदोलन और जागरूकता की स्थायी संस्कृति को प्रेरित करने की उम्मीद है।" कासोदकर को 60 दिनों में 60 मैराथन दौड़ने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 555 किलोमीटर लंबी ला अल्ट्रा दौड़ दौड़ने के लिए जाना जाता है।

वह अरुणाचल प्रदेश और असम से लेकर बिहार तक तथा उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात तक कई राज्यों की यात्रा कर रहे हैं। इस दौड़ के दौरान डॉन2डस्क का लक्ष्य ग्रो ट्री फ़ाउंडेशन के साथ मिलकर 76,000 पेड़ लगाना और देश भर के नागरिकों का अपने-अपने स्थानों से सामूहिक रूप से 7,60,000 किलोमीटर दौड़ना और पैदल चलना है।

हेजलवुड को रिहैब के दौरान नई चोट, एड़ी में 'लो-ग्रेड' इंजरी से एशेज में वापसी संदिग्ध

ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड एक बार फिर चोट की वजह से मुश्किल में पड़ गए हैं। हैमस्ट्रिंग इंजरी से उबरने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें अब "लो-ग्रेड अकिलीस इंजरी" हुई है। इसके बाद एशेज सीरीज़ के बचे हुए मुकाबलों में उनकी उपलब्धता पर सवाल खड़े हो गए हैं। गाबा में जारी डे-नाइट टेस्ट के दूसरे दिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने हेजलवुड की फिटनेस को लेकर आधिकारिक अपडेट जारी किया।

बयान में कहा गया, "जोश हेज़लवुड ने इस सप्ताह अपनी हैमस्ट्रिंग चोट से रिकवरी के दौरान अकिलीस में दर्द की शिकायत की। यह लो-ग्रेड समस्या है और अगले सप्ताह उनसे दोबारा रनिंग और बॉलिंग शुरू करने की उम्मीद है।" हालांकि हेज़लवुड के ठीक होने का स्पष्ट टाइमलाइन तय नहीं है और यह

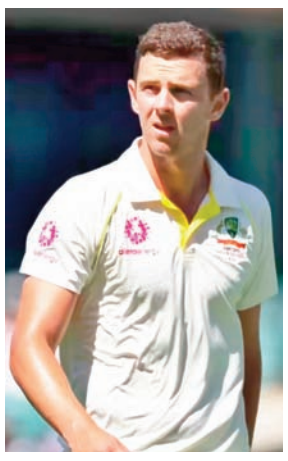

इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी एड़ी की समस्या कितनी जल्दी सुधरती है। गौरतलब है कि हेज़लवुड पिछले महीने शेफ़ील्ड शील्ड में न्यू साउथ वेल्स की तरफ से खेलते हुए हैमस्ट्रिंग चोटिल हुए थे। शुरुआती स्कैन में सब सामान्य था, लेकिन दोबारा जांच में चोट की पुष्टि हुई, जिसके चलते वे एशेज सीरीज़ के पहले दो टेस्ट मैचों से बाहर हो गए। इस सप्ताह उन्हें ब्रिस्बेन आकर टीम के साथ रिकवरी जारी करनी थी, लेकिन दर्द बढ़ने पर यह यात्रा रद्द कर दी गई। वे फिलहाल सिडनी में ही रहेंगे, जिससे उनके बचे हुए मैचों में खेलने की संभावना कमजोर हो गई है।

पहले ऐसा माना जा रहा था कि हेजलवुड 17 दिसंबर से एडिलेड में होने वाले तीसरे टेस्ट से वापसी कर सकते हैं और उन्होंने रेड-बॉल बॉलिंग पर केंद्रित सत्र भी शुरू किया था, लेकिन ताज़ा चोट ने उनकी वापसी को फिर अनिश्चित बना दिया है। अब आशंका है कि वह चौथे टेस्ट से पहले उपलब्ध नहीं होंगे और यदि पूरा एशेज मिस करते हैं, तो यह 2014 में डेब्यू के बाद पहली बार होगा जब वह किसी एशेज में एक भी टेस्ट नहीं खेल पाएंगे।

रोहित-कोहली से फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद

विशाखापत्तनम। भारत विराट कोहली और रोहित शर्मा से फिर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुक्रवार को यहां होने वाले तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जीत हासिल करके श्रृंखला अपने नाम करने की कोशिश करेगा। भारत के कुछ युवा खिलाड़ी अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और ऐसे में उन पर दबाव होगा। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट श्रृंखला जीतने के बाद अब वनडे श्रृंखला जीतने में भी कसर नहीं छोड़ेगा और ऐसे में भारतीय टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की जरूरत है। भारत अगर इस मैच में जीत हासिल करता है तो पिछले कुछ समय से टीम को लेकर चल रही अटकलें पर भी विराम लग जाएगा। इसके लिए कोहली और रोहित को फिर से अपना महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन दोनों का वनडे क्रिकेट में कोई सानी नहीं है और उन्हें इस तरह के दबाव

वाले मैच में खेलने का अच्छा अनुभव है। इसलिए भारत की जीत में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। रोहित और कोहली अपनी करियर के अवसान पर हैं और वह इसमें एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने की कोशिश करेंगे। कोहली ने अपनी पिछली तीन पारियों में दो शतक और एक अर्धशतक लगाया है, जबकि रोहित ने अपनी पिछली चार पारियों में एक शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं। उन्हें कुछ युवा बल्लेबाजों का अच्छा सहयोग मिल रहा है जैसा कि पिछले मैच में रुतुराज गायकवाड़ ने अपना योगदान दिया था। उन्होंने अपना पहला वनडे शतक लगाया था। लेकिन यशस्वी जायसवाल को अभी भी इस श्रृंखला में सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन करना बाकी है। यह प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने के लिए उत्सुक होगा। जायसवाल को बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ जूझना पड़ रहा है फिर चाहे वह वेस्टइंडीज के जेडन सील्स हों या इस श्रृंखला में मार्को यानसन और नांद्रे बर्गर। वह अपने करियर में 30 बार बाएं हाथ के गेंदबाजों का शिकार बने हैं। जायसवाल और टीम प्रबंधन इससे अनजान नहीं रह सकते और इसमें सुधार करने का काम शायद पहले ही शुरू हो चुका है। लेकिन अगर वह सुधार नहीं कर पाए तो टीम को अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। टीम के पास गायकवाड़ के रूप में एक अदद सलामी बल्लेबाज मौजूद है। एसीए-वीडीसीए स्टेडियम की पिच अक्सर बल्लेबाजों के अनुकूल होती है और भारत का यहां शानदार रिकॉर्ड रहा है। उसने यहां 2005 से 10 एकदिवसीय मैचों में से सात में जीत हासिल की है लेकिन यहां खेले गए पिछले मैच में उसे आस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। भारत वाशिंगटन सुंदर को विश्राम देकर उनकी जगह तिलक वर्मा को मध्यक्रम की बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए अंतिम एकादश में शामिल करने पर भी गंभीरता से विचार करेगा। ऋषभ पंत भी एक विकल्प हो सकते हैं लेकिन तिलक स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं और वह बेहतरीन क्षेत्ररक्षक के भी हैं। कप्तान केएल राहुल ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन इस श्रृंखला में ओस के कारण टॉस की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। भारत वनडे में पिछले 20 मैच से टॉस नहीं जीत पाया है जिसका खामियाजा उसे रायपुर में दूसरे वनडे में भुगतना पड़ा। भारतीय गेंदबाज भी अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अब भारत को उम्मीद होगी कि उनके युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा अच्छा प्रदर्शन करेंगे और प्रभावशाली अर्शदीप सिंह का पूरा साथ देंगे। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला जीतने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन वह तेज गेंदबाज बर्गर और बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी की फिटनेस को लेकर चिंतित है। यह देखना होगा कि ये दोनों खिलाड़ी इस मैच के लिए पूरी तरह फिट हो पाते हैं या नहीं।

कारोबार

RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान घटाकर 2% किया

संक्षिप्त खबरें

UPI को मंजूरी के लिए आठ अन्य देशों के साथ बातचीत जारी: वित्तीय सेवा सचिव

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त सेवा सचिव एम. नागराजू ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपने डिजिटल भुगतान मंच यूपीआई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य बनाने के लिए आठ देशों के साथ बातचीत कर रहा है। फिलहाल भारत की लोकप्रिय भुगतान प्रणाली यूपीआई को आठ देशों में स्वीकार्य किया गया है। इनमें भूटान, सिंगापुर, कतर, मॉरीशस, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), श्रीलंका और फ्रांस शामिल हैं। इससे भारतीय पर्यटक विदेशों में लेन-देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। नागराजू ने यहां एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ₹हम अब यूपीआई लेनदेन को संभव बनाने के लिए करीब सात-आठ देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं जिनमें पूर्वी एशिया के कई देश शामिल हैं।₹ उन्होंने बताया कि भारत कुछ देशों के साथ व्यापार वार्ताओं के दौरान यूपीआई को भी शामिल कर रहा है। नागराजू ने कहा, ₹कुछ देशों के साथ जिन व्यापार वार्ताओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें यूपीआई का भी एक पहलू रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र में गहराई से शामिल वित्तीय-प्रौद्योगिकी उद्योग भी इसमें अपनी भूमिका निभा सके।₹ उन्होंने कहा कि भारत को लागत और पैमाने के स्तर पर बढ़त हासिल है और इस लाभ का उपयोग देश के हित में करना चाहता है।

एलन मस्क के सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर 12 करोड़ यूरो का जुर्माना

लंदन। यूरोपीय संघ के नियामकों ने शुक्रवार को एलन मस्क के सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर डिजिटल नियमों का पालन न करने के लिए 12 करोड़ यूरो (लगभग 14 करोड़ डॉलर) का जुर्माना लगाया। यूरोपीय आयोग ने यह निर्णय दो साल पहले सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) के खिलाफ शुरू की गई जांच के बाद लिया है। यह जांच 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम (डीएसए) के तहत की गई थी। डीएसए एक व्यापक कानून है जो सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मंच से कहता है कि यूरोप के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए वे ज्यादा जिम्मेदारी लें और अपनी साइट पर आने वाली हानिकारक या गैर-कानूनी सामग्री तथा उत्पादों को तुरंत हटाएं। अगर वे ऐसा नहीं करते तो बहुत भारी जुर्माना लग सकता है। आयोग ने कहा कि वह सोशल मीडिया मंच एक्स को डीएसए की पारदर्शिता आवश्यकताओं के तीन अलग-अलग उल्लंघनों के कारण दंडित कर रहा है। नियामकों ने कहा कि 'एक्स' के नीले टिक निशान नियमों का उल्लंघन करते हैं क्योंकि उनका भ्रामक डिजाइन उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी और गलत जानकारी के जोखिम में डाल सकता है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को 2.6 प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया है। मुद्रास्फीति के लक्ष्य को लेकर 2016 में लचीली व्यवस्था अपनाये जाने के बाद पहली बार हेडलाइन (खुदरा) मुद्रास्फीति 2025-26 की दूसरी तिमाही में औसतन 1.7 प्रतिशत रही। यह आरबीआई को दिये गये लक्ष्य के निचले स्तर दो प्रतिशत से भी कम है। आरबीआई को दो प्रतिशत घट बढ़ के साथ मुद्रास्फीति चार प्रतिशत (दो से छह प्रतिशत) रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। यह अक्टूबर 2025 में और भी घटकर केवल 0.3 प्रतिशत पर आ गई जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की तीन-दिवसीय बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, '' मुद्रास्फीति में अनुमान से अधिक तेजी से गिरावट खाद्य कीमतों में सुधार के कारण आई। यह सितंबर-अक्टूबर के महीनों के दौरान देखी जाने वाली सामान्य प्रवृत्ति के उलट है। कीमती धातुओं द्वारा निरंतर मूल्य दबाव के बावजूद मुख्य मुद्रास्फीति (खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति) सितंबर-अक्टूबर में काफी हद तक नियंत्रित रही।'' सोने को छोड़कर अक्टूबर में मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई। गवर्नर ने कहा कि कुल मिलाकर मुद्रास्फीति काफी गिरावट आ गई है। मुद्रास्फीति परिदृश्य पर मल्होत्रा ने कहा कि उच्च खरीफ उत्पादन, अच्छी रबी बुवाई, जलाशयों के पर्याप्त स्तर एवं मिट्टी में अनुकूल नमी से खाद्य आपूर्ति की संभावनाएं बेहतर हुई हैं। उन्होंने कहा कि कुछ धातुओं को छोड़कर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिंस की कीमतों में आगे चलकर नरमी आने की संभावना है। गवर्नर ने कहा, '' कुल मिलाकर मुद्रास्फीति अक्टूबर में लगाए गए अनुमान से कम रहने की संभावना है। इसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में गिरावट है।'' इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए मल्होत्रा ने कहा कि 2025-26 के लिए खुदरा (सीपीआई) मुद्रास्फीति अब दो प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके तीसरी तिमाही में 0.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 2026-27 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मल्होत्रा ने कहा कि अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबाव और भी कम है क्योंकि कीमती धातुओं की कीमत में वृद्धि का प्रभाव लगभग 0.50 प्रतिशत है जिसमें जोखिम दोनों ओर समान है।

रुपये की कीमत का लक्षित स्तर या दायरा नहीं, खुद पाएगा अपना सही स्तर: RBI गवर्नर

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपये के लिए कोई लक्षित स्तर या दायरा नहीं रखता है और घरेलू मुद्रा को खुद ही अपना 'सही स्तर' खोजने की अनुमति देता है।

मल्होत्रा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रुपया इसी हफ्ते अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के स्तर को पार कर अपने सबसे निचले भाव पर पहुंच गया। बृहस्पतिवार को इसने 90.43 रुपये प्रति डॉलर का रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ था। मल्होत्रा ने कहा, "हम रुपये के लिए मूल्य का कोई स्तर या दायरा नहीं रखते हैं। हम बाजारों को ही कीमतें तय करने देते हैं। लंबी अवधि में बाजार काफी प्रभावी होते हैं। यह एक बहुत बड़ा बाजार है।" उन्होंने कहा कि बाजार में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं और आरबीआई का प्रयास

हमेशा असामान्य या अत्यधिक उतार-चढ़ाव को कम करना होता है। आरबीआई ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में इस महीने पांच अरब अमेरिकी डॉलर की तीन-वर्षीय डॉलर/रुपया खरीद-बिक्री अदला-बदली करने का फैसला किया है।

इस कदम पर मल्होत्रा ने कहा कि यह रुपये की गिरावट को रोकने का प्रयास नहीं है बल्कि यह एक नकदी उपाय है। यह कदम रुपये को समर्थन देने के लिए नहीं है। आरबीआई डॉलर-रुपया खरीद-बिक्री अदला-बदली के तहत बैंकों से डॉलर खरीदता है और बाद में उन्हें वापस बेचने के लिए सहमत होता है। इसका मकसद रुपये में तरलता बढ़ाना, विनिमय दरों का प्रबंधन करना और बैंकों को विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं का प्रबंधन करने में मदद करना है। मल्होत्रा ने कहा कि देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार हैं और चालू खाता भी संतुलित है।

मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे के चलते आगे अच्छी पूंजी प्रवाह की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष में तीन दिसंबर तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में 70 करोड़ डॉलर की शुद्ध निकासी हुई है जो मुख्य रूप से इक्विटी खंड से निकासी का नतीजा है। इसके अलावा, बाह्य वाणिज्यिक ऋण और गैर-निवासी जमा खाते में प्रवाह भी पिछले वर्ष की तुलना में मध्यम रहा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 28 नवंबर तक 686.2 अरब डॉलर पर था जो 11 माह से अधिक के आयात खर्च के लिए पर्याप्त है।

RBI लोकपाल के पास लंबित शिकायतों के समाधान के लिए अभियान शुरू करेगा

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल के पास एक महीने से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों के समाधान के लिए जनवरी से दो महीने का अभियान शुरू करेगा। आरबीआई लोकपाल के पास बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होने के परिणामस्वरूप लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ यह कदम उठाया गया है। आरबीआई लोकपाल योजना बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों समेत केंद्रीय बैंक के दायरे में आने वाले वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहक शिकायतों का बिना किसी लागत के समाधान करने में मदद करती है।

समस्याओं का समाधान ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है या बैंक 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है तो लोकपाल में उसकी शिकायत की जा सकती है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन-दिवसीय बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि हम ग्राहक सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

हमने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। फिर से केवाईसी, वित्तीय समावेश और 'आपकी जानकारी, आपका अधिकार' अभियान अन्य हितधारकों के सहयोग से की गई कुछ पहलों में से हैं।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में, हमने अपने नागरिक 'चार्टर' की भी समीक्षा की थी। हम हर महीने की पहली तारीख को अपने मासिक निपटान और विभिन्न आवेदनों के लंबित रहने के बारे में जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं। मल्होत्रा ने कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि 99.8 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर दिया गया है। गवर्नर ने कहा कि मैं सभी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आरबीआई के दायरे में आने वाली वित्तीय संस्थानों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी नीतियों तथा कार्यों में ग्राहकों को केंद्र में रखें। ग्राहक सेवा में सुधार करें और शिकायतों को कम करें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हम अगले महीने जनवरी से दो माह का अभियान चलाने का प्रस्ताव रखते हैं। इसका मकसद आरबीआई लोकपाल के पास एक महीने से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों का समाधान करना है।

रेपो दर में कटौती से शेयर बाजार में उत्साह, सेंसेक्स 447 अंक उछला

मुंबई। रेपो दर में कटौती और नकदी बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक के नीतिगत कदमों की घोषणा के बाद शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में खासी तेजी रही। मानक सूचकांक सेंसेक्स 447 अंक उछल गया जबकि निफ्टी में 153 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स 447.05 अंक यानी 0.52 प्रतिशत चढ़कर 85,712.37 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 531.4 अंक तक उछल गया था। एनएसई का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी भी 152.70 अंक यानी 0.59 प्रतिशत बढ़कर 26,186.45 अंक पर पहुंच गया। यह शेयर बाजार में तेजी का लगातार दूसरा दिन रहा। बृहस्पतिवार को भी दोनों मानक सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए थे। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर इसे 5.25 प्रतिशत कर दिया।

डीजीसीए प्रमुख ने सुचारू उड़ान संचालन सुनिश्चित करने के लिए पायलटों से मांगा सहयोग

मुंबई। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के महानिदेशक फैज अहमद किदवई ने शुक्रवार को इंडिगो के परिचालन में बड़े पैमाने पर पैदा हुए व्यवधान के बीच उड़ानों के सुचारू संचालन के लिए सभी पायलटों से सहयोग का अनुरोध किया। किदवई ने अपनी अपील में कहा कि परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण इंडिगो की वर्तमान उड़ान बाधाओं, अप्रत्याशित मौसम और बढ़ती मांग के कारण विमानन क्षेत्र इस समय काफी दबाव का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन व्यवधानों के कारण देरी हुई है, यात्रियों को असुविधा हुई है और विमानों के संचालन पर दबाव बढ़ा है। किदवई ने कहा, ''अब कोहरे के मौसम, छुट्टियों और शादियों के मौसम को देखते हुए यह जरूरी है कि उद्योग और भी बड़ी परिचालन चुनौतियों के लिए तैयार रहे। यात्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है। मौसम संबंधी प्रभाव उड़ान सेवाओं के समय-निर्धारण एवं उनकी सुरक्षा को अधिक जटिल बना सकते हैं।'' उन्होंने स्थिति को सक्रियतापूर्वक एवं सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए पायलट और विमानन कंपनियों के बीच समन्वय को मजबूत करने की जरूरत पर भी बल दिया। उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) मानदंडों में ढील को लेकर कुछ हलकों में व्याप्त चिंताओं के बीच डीजीसीए ने कहा कि वह 'एफडीटीएल के नागर विमानन प्रावधानों को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।' संशोधित एफडीटीएल नियमों का दूसरा चरण एक नवंबर से लागू हुआ है। इसके लिए समय से तैयारी नहीं कर पाने की वजह से इंडिगो में चालक दल की बड़े पैमाने पर कमी सामने आई है।

फिल्म 'तेरे इश्क में' की सफलता पर भावुक हुईं कृति सेनन

मुंबई। कृति सेनन और धनुष की ताज़ा रिलीज़ फिल्म 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। दर्शकों के प्यार और बेहतरीन कमाई ने फिल्म की टीम का उत्साह बढ़ा दिया है। खासकर कृति सेनन की एक्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जिसके बाद फैंस अभिनेत्री को हिंदी सिनेमा की उभरती हुई और दमदार परफॉर्मर बता रहे हैं। फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए किरदार 'मुक्ति' को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से खूब सराहना मिल रही है। इसी फैन लव को महसूस करते हुए कृति सेनन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें कई इंफ्लुएंसर्स और फिल्म क्रिटिक्स उनकी एक्टिंग की खुलकर तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि मुक्ति का किरदार कई परतों वाला और भावनात्मक रूप से बेहद पेचीदा था, जिसे कृति ने न सिर्फ ईमानदारी से निभाया, बल्कि पर्दे पर उसे जीवंत बना दिया। कई समीक्षा देने वालों का यह भी मानना है कि इस रोल को कृति जितनी बारीकी और संवेदनशीलता के साथ कोई और अभिनेत्री निभा ही नहीं पाती। इतनी भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ देखकर कृति सेनन खुद भी भावुक हो गईं और उन्होंने दिल से अपने दर्शकों का धन्यवाद किया।

पति आदित्य की फिल्म 'धुरंधर' के रिलीज के दिन भावुक हुईं यामी गौतम

मुंबई। विवादों के बाद फाइनली रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, और सारा अर्जुन स्टारर फिल्म 'धुरंधर' शुक्रवार को रिलीज हुई है। फिल्म का निर्माण और डायरेक्शन दोनों ही आदित्य धर ने किया है। अब पति आदित्य के महत्वपूर्ण दिन पर यामी गौतम ने उनकी मेहनत को सराहा है और दर्शकों से भी फिल्म पर ढेर सारा आशीर्वाद लुटाने की अपील की है। यामी गौतम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पति आदित्य के साथ एक प्यारा सा फोटो शेयर किया है। उन्होंने पोस्ट में आदित्य की मेहनत का भी जिक्र किया है कि कैसे एक फिल्म बनाने में उन्होंने खुद को पूरा समर्पित कर दिया। उन्होंने लिखा, "आज धुरंधर दिवस है। कुछ सबसे मेहनती और अनमोल लोग जिन्हें मैं जानती हूं और उन्हें अपना परिवार कहने पर गर्व करती हूं, आपने अपना पूरा दिल, समर्पण, लगन, इरादा, जुनून, पसीना, खून, आंसू इस फिल्म के लिए दिए हैं, आदित्य। ये इमोशन आपने कभी किसी के सामने नहीं दिखाए।" उन्होंने आगे लिखा, "आज बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही हैं, कई दिल एक साथ धड़क रहे हैं, आप लोग अपनी शक्ति में धुरंधर हैं। धुरंधर 2025 का विदाई गिफ्ट नहीं है, बल्कि दुनिया भर में हम सभी इसे 2026 के स्वागत के रूप में देखेंगे। अब यह आपकी फिल्म है, दर्शकों। बता दें कि फिल्म 'धुरंधर' को बनाने में आदित्य धर ने लगभग 2-3 साल का वक्त लिया था। पहले उन्होंने फिल्म के लिए बहुत सारी रिसर्च की और फिर फिल्म की स्टारकास्ट को फाइनल करने में बहुत मेहनत की। फिल्म 'धुरंधर' का हर किरदार अपने आप में अलग है और सबकी कहानी भी अलग है। फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन बाकी किरदार किसी न किसी से प्रेरित हैं। माना जा रहा है कि रणवीर सिंह के लिए ये फिल्म करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकती है। 'धुरंधर' के मल्टीस्टारर होने के बाद भी फिल्म का सारा फोकस रणवीर के किरदार पर है। फिल्म को देशभक्ति से प्रेरित बताया जा रहा है, जिसमें रणवीर सिंह की एक्टिंग की तारीफ हो रही है। फिल्म के प्रीमियर के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अब देखना होगा कि फिल्म शुक्रवार को पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग कर पाती है।

अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने बताया कैसे बदली अपनी जिंदगी और सोच

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा आज अपनी निडर आवाज, बेबाक बयानों और मजबूत व्यक्तित्व के लिए पहचानी जाती हैं, लेकिन अभिनेत्री का कहना है कि वे हमेशा से ऐसी नहीं थीं। मुंबई में आयोजित 15वें इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट में उन्होंने अपने शुरुआती संघर्षों और उस दौर के दर्दनाक अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि एक समय ऐसा भी था जब वे बेहद डरपोक, समझौतावादी और खुद को कम आंकने वाली इंसान बन चुकी थीं। आज भले ही लोग उन्हें आत्मविश्वास और साहस की प्रतीक मानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे का सच बिल्कुल अलग था। ऋचा ने एक घटना याद करते हुए बताया कि करियर की शुरुआत में उन्हें कई ऐसे काम स्वीकार करने पड़े जिन्हें करने में उन्हें असहजता महसूस होती थी। उन्होंने कहा, "एक दिन मैं सेट पर खड़ी थी और मैंने खुद से पूछा मैंने ये फिल्म कब साइन की? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं इस आइटम नंबर में क्यों हूँ? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ और कैसे फँस गई हूँ।" उन्होंने बताया कि एक डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि मेल कोरियोग्राफर चाहिए और तुम्हें 'ऐसे-वैसे' करना है। यह सुनकर वे अंदर से टूट गईं और सोचने लगीं कि आखिर वे यहाँ तक कैसे पहुँच गईं। उन्हें बाद में अहसास हुआ कि किसी लोकल मैनेजर ने कुछ पैसे लेकर गलत रास्ते पर धकेल दिया था। अभिनेत्री ने कहा कि इंडस्ट्री में कई लोग उनकी बाहरी सुंदरता पर टिप्पणी करते थे और उन्हें बदलने की सलाह देते थे। ऋचा ने कहा, "मुझसे कहा जाता होंठ ठीक करवा लो, नाक ठीक करवा लो, चेहरे पर सुधार करवाओ, गाना शूट करने से पहले पानी मत पीना। मैं हर बात मान लेती थी। मैं अपने शरीर और दिमाग को बहुत चोट पहुँचा चुकी थी। मैं खुद से कहती थी मैं बेकार हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ।" उन्होंने बताया कि मनोरंजन जगत में कई लोग दूसरों को छोटा महसूस करवाकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। अपने बदलाव की प्रक्रिया पर बात करते हुए ऋचा ने कहा कि अपनी आवाज उठाना उन्होंने धीरे-धीरे सीखा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने खुद को स्वीकार करना शुरू किया, तब उन्हें समझ आया कि किसी भी कीमत पर आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। आज वे मानती हैं कि किसी कलाकार का सबसे बड़ा साहस अपनी सच्चाई पर डटे रहना होता है।

विदेश

संक्षिप्त खबरें

पुतिन के करीबी की संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए एक कंपनी पर 71 लाख डॉलर का जुर्माना

वाशिंगटन। अमेरिका के वित्त विभाग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी उद्योगपति ओलेग देरिपस्का की आलीशान रियल एस्टेट संपत्तियों का प्रबंधन करके पाबंदियों का उल्लंघन करने के आरोप में न्यूयॉर्क में स्थित एक कंपनी पर 71 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है। वित्त विभाग के विदेशी संपत्तियां नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने कहा कि ग्रेसटाउन इंक नामक संपत्ति प्रबंधन कंपनी को देरिपस्का के स्वामित्व वाली एक कंपनी की ओर से अप्रैल 2018 से मई 2024 के बीच 24 बार भुगतान के जरिये कुल 31,250 अमेरिकी डॉलर की राशि हासिल हुई। ओएफएसी ने कहा कि उसने ग्रेसटाउन को नोटिस जारी कर कहा था कि देरिपस्का के साथ लेनदेन पर प्रतिबंध है, लेकिन कंपनी लेनदेन करती रही। देरिपस्का 2018 से आर्थिक पाबंदियों का सामना कर रहे हैं जब वित्त मंत्रालय ने उन पर वरिष्ठ रूसी अधिकारियों के इशारे पर काम करने और रूस के ऊर्जा क्षेत्र में कारोबार करने का आरोप लगाया था। इसके बाद अमेरिका में उनकी संपत्तियों पर रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा अमेरिकी नागरिक और कंपनियां भी पाबंदियों के तहत देरिपस्का के साथ कामकाज नहीं कर सकतीं।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्कूली छात्राओं पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप, जांच शुरू

कराची। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कुछ हिंदू स्कूली छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने के लिए कथित तौर पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा गया, जिसके बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नवंबर के अंत में, सिंध के मिरपुर साक्रो में स्थित सरकारी उच्च विद्यालय की कुछ हिंदू छात्राओं के माता-पिता ने मीडिया को बताया था कि स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने कथित रूप से हिंदू छात्राओं से कहा था कि वे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए इस्लाम धर्म अपना लें। माता-पिता ने आरोप लगाया कि हिंदू छात्राओं को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और उनके धर्म का मजाक उड़ाया गया। इस आरोप के बाद आक्रोश फैल गया। माता-पिता ने यह दावा भी किया कि इस्लाम धर्म अपनाने या कलमा पढ़ने से इनकार करने पर कुछ छात्राओं को उनके घर लौटा दिया गया। धार्मिक मामलों के राज्य मंत्री खीसो मल खील दास ने बृहस्पतिवार को संसद के उच्च सदन सीनेट को बताया कि प्रांतीय शिक्षा मंत्री ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है।

आपदा मोचन बल ने चक्रवात प्रभावित श्रीलंका में खोज और बचाव अभियान पूरा किया

कोलंबो। चक्रवात दित्वा से प्रभावित श्रीलंका में खोज, बचाव और राहत अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम शुक्रवार को स्वदेश रवाना हो गयीं। भारतीय उच्चायोग ने यह जानकारी दी। श्रीलंका चक्रवात दित्वा के कारण व्यापक बाढ़, भूस्खलन और बुनियादी ढांचे के ध्वस्त होने के संकट से जूझ रहा है। इस आपदा के कारण शुक्रवार तक 450 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, कई जिलों का संपर्क टूट गया है तथा देश की आपदा मोचन क्षमता पर भी गंभीर दबाव पड़ा है। श्रीलंका की ओर से सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय अपील किए जाने पर भारत 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत मदद पहुंचाने वाला पहला देश रहा। भारतीय उच्चायोग ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम में 80 कर्मी और के9 (श्वान दस्ते) इकाइयां शामिल थीं। ये टीम 29 नवंबर को श्रीलंका पहुंचीं और ₹उन्हें तुरंत सबसे बुरी तरह प्रभावित कुछ क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया।₹ उच्चायोग ने बताया कि श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय और उनके मार्गदर्शन में काम करते हुए

एनडीआरएफ ने कई जिलों में व्यापक अभियान चलाए। उसने कहा, ''अपना अभियान सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एनडीआरएफ की टीम आज कोलंबो से रवाना हुई।₹ उसने बताया कि इन टीम ने बादुल्ला, कोच्चिकड़े, पुट्टलम, कोलंबो और गम्पाहा में बाढ़ एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर बचाव कार्य किया। उच्चायोग ने बताया कि टीम के कार्यों में जलमग्न इलाकों में पहुंचना, फंसे हुए परिवारों तक पहुंचना, क्षतिग्रस्त इमारतों में फंसे लोगों की सहायता करना, मृत लोगों को निकालना, सहायता वितरित करना और जहां आवश्यक हो वहां तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना शामिल थे। उसने कहा कि टीम ने लगभग 150 लोगों को बचाया, कई शवों और फंसे हुए जानवरों को निकाला है। उसने कहा कि ₹खतरनाक स्थितियों, क्षतिग्रस्त मार्गों और अस्थिर भौगोलिक स्थिति वाले इलाकों के बावजूद₹ उन्होंने सहायता की हर अपील पर ध्यान दिया। उच्चायोग ने कहा कि उन्होंने गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, दिव्यांगजनों और अन्य जरूरतमंदों की भी सहायता की है। उसने बताया कि भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से एक बादुल्ला जिले में एनडीआरएफ कर्मियों ने विशेष उपकरणों और 'के9' खोज सहायता के साथ लंबी दूरी पैदल तय की। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र द्वारा शुक्रवार सुबह जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, 16 नवंबर से मौसम खराब होने के कारण आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 486 लोगों की मौत हो गई तथा 341 लापता हैं। इसके अलावा, भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका के आवास एवं निर्माण मंत्री से मुलाकात कर चक्रवात दित्वा के बाद पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास प्रयासों पर चर्चा की। भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''दोनों ने चक्रवात दित्वा के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवास क्षेत्र में भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत विकास सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की।'' आंकड़ों के अनुसार, चक्रवात के बाद 2,303 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं जबकि 52,489 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

हेगसेथ ने गोपनीय सैन्य योजना साझा कर सैनिकों को खतरे में डाला: पेंटागन

वाशिंगटन। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यमन में हूती विद्रोहियों पर होने वाले सैन्य हमले से संबंधित संवेदनशील योजनाएं अपने निजी फोन से साझा करके अमेरिकी सैनिकों को जोखिम में डाल दिया। पेंटागन के महानिरीक्षक की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय में अनुमोदित नहीं किए गए मैसेजिंग ऐप और उपकरणों के उपयोग की भी आलोचना की गई है। निरीक्षक ने पाया कि हेगसेथ के पास 'सिग्नल चैट' नामक मैसेजिंग ऐप में साझा की गई जानकारी को 'डी-क्लासिफाई' यानी गोपनीय श्रेणी से हटाने का अधिकार था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हूती विद्रोहियों पर होने वाले हमले का संवेदनशील विवरण जारी करना, पेंटागन के आंतरिक नियमों का उल्लंघन है। इससे अभियान में शामिल सदस्यों या उनके मिशन को खतरा हो सकता था। रिपोर्ट के अनुसार, हेगसेथ द्वारा साझा की गई जानकारी में अमेरिकी विमानों के उड़ान समय और संख्या जैसे विवरण थे, जिसने परिचालनीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा किया। रिपोर्ट के अनुसार इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी अभियान विफल हो सकता था और अमेरिकी पायलटों को संभावित नुकसान पहुंचने की आशंका थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि यह जानकारी दुश्मनों के हाथ लग जाती, तो हूती सुरक्षा बल अमेरिकी हमलों से बचने के लिए अपने लड़ाकों और संसाधनों को नए सिरे से तैनात कर सकते थे। हेगसेथ ने इस रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि ₹कोई गोपनीय जानकारी नहीं थी। पूरी तरह निर्दोष हूं। बात खत्म।₹ हालांकि, डेमोक्रेटिक सांसदों ने हेगसेथ के कार्यों को ₹लापरवाही भरा₹ बताया है और कहा है कि अगर किसी निचले स्तर के सैन्य अधिकारी ने ऐसा किया होता, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता या कड़ी सजा दी जाती। महानिरीक्षक कार्यालय ने सूचना सुरक्षा को लेकर रक्षा विभाग के कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण देने की सिफारिश की है।

ईरान ने होर्मुज खाड़ी में सैन्य अभ्यास के दौरान बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी

तेहरान। ईरान की नौसेना ने अपने युद्धाभ्यास के दूसरे दिन ओमान सागर और रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य के पास बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागीं। सरकारी टेलीविजन चैनल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सरकारी टीवी चैनल ने खबर दी कि अर्धसैनिक बल 'रिवोल्यूशनरी गार्ड' ने बृहस्पतिवार को शुरू हुए युद्धाभ्यास के तहत ईरान की मुख्य भूमि के भीतरी हिस्सों से मिसाइलें दागीं और ओमान सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट पड़ोसी क्षेत्र में तय लक्ष्यों पर निशाना साधा। खबर के मुताबिक अभ्यास के दौरान कद्र-110, कद्र-380 और गदीर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया जिनकी मारक क्षमता 2,000 किलोमीटर (1,250 मील) तक है। इसने कहा कि रिवोल्यूशनरी गार्ड ने '303' नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की है, हालांकि इस बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है। टेलीविजन चैनल पर प्रसारित तस्वीरों में मिसाइलों के प्रक्षेपण और लक्ष्यों पर उनके प्रहार को दिखाया गया है। यह

युद्धाभ्यास जून में इजराइल-ईरान युद्ध के बाद दूसरा इस तरह का सैन्य अभ्यास है। युद्ध के दौरान ईरान के सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों सहित लगभग 1,100 लोग मारे गए थे। ईरान के मिसाइल हमलों में इजराइल में 28 लोग मारे गए थे। ईरान लंबे समय से होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी देता रहा है, जिसके जरिये दुनिया का करीब 20 प्रतिशत व्यापार होता है। अमेरिकी नौसेना लंबे समय से अपने बहरीन स्थित पांचवें बेड़े के माध्यम से इलाके में गश्त करती आ रही है।

जर्मनी की संसद ने सैनिकों की अधिक भर्ती वाली योजना को दी मंजूरी

बर्लिन। जर्मनी की संसद ने रूस से बढ़ते खतरे के मद्देनजर अपने सशस्त्र बलों में सैनिकों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश के तहत शुक्रवार को एक योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना में युवाओं के लिए अनिवार्य चिकित्सा जांच का भी प्रावधान है। वैसे इस योजना में अनिवार्य सैन्य भर्ती पर रोक है लेकिन जरूरत पड़ने पर कम से कम सीमित संख्या में अनिवार्य सैन्य सेवा की संभावना का विकल्प खुला रखा गया है। संसद के निचले सदन 'बुंडेस्टाग' में 272 के मुकाबले 323 मतों से इस योजना को मंजूरी दी गयी जबकि एक सदस्य ने मत विभाजन में हिस्सा नहीं लिया। यह चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त में पारित की गई एक परियोजना का संशोधित संस्करण है। जर्मनी ने वर्षों की उपेक्षा के बाद अपनी सेना के उपकरणों को बेहतर बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने का निर्णय लिया है।

ब्रिटेन में अवैध रूप से काम करने के आरोप में पकड़े गए लोगों में भारतीय भी शामिल

लंदन। ब्रिटेन में व्यापक स्तर पर की गई कार्रवाई में अवैध रूप से काम करते पकड़े गए 171 लोगों में भारतीय भी शामिल हैं। इन्हें देश से बाहर भेजने के लिए हिरासत में लिया गया है। ब्रिटेन सरकार ने यह जानकारी दी। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की आव्रजन प्रवर्तन टीम ने पिछले महीने सात दिन तक 'ऑपरेशन इक्वलाइज' चलाया, जिसमें ब्रिटेन के गांवों, कस्बों और शहरों में सामान पहुंचाने का काम करने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच की गई। अवैध रूप से काम करते पाए गए (जिनमें बांग्लादेशी और चीनी नागरिक भी शामिल थे) लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनके मूल देशों में भेजने के लिए हिरासत में ले लिया गया। गृह मंत्रालय के कार्यालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, ₹17 नवंबर को, न्यूहैम (पूर्वी लंदन) के हाई स्ट्रीट पर अधिकारियों को तैनात किया गया था। बांग्लादेशी और भारतीय नागरिकता वाले चार लोगों को अवैध रूप से काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चारों को वापस भेजने के लिए हिरासत में लिया गया₹। इसने गिरफ्तार किए गए कुल 171 लोगों का ब्योरा दिया। इसमें कहा गया, ₹और 25 नवंबर को अधिकारी नॉर्विच सिटी सेंटर (पूर्वी इंग्लैंड) पहुंचे, जहां उन्होंने अपराध नियंत्रण अभियान चलाया। सामान पहुंचाने का काम करने वाले भारतीय नागरिकता वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और दो को देश से बाहर भेजने के लिए हिरासत में लिया गया। तीसरे व्यक्ति को सख्त आव्रजन जमानत पर रखा गया।